04 - बिहार से नीतीश कुमार की विदाई के मायने

05 - जिम्मेदार नागरिक बनने का वक्त

A Daily News Magazine

इंदौर

शनिवार, 14 मार्च, 2026

06 - 'विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए , संकल्प एक ही रखना...

07 - विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं : अपर मुख्य सचिव.

इंदौर एवं भोपाल से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 11 अंक 160, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com

facebook.com/subahsaverenews

www.subahsavere.news

twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

तुम्हारा प्यार
एक झील है
जिसमें मैं
नहाता रहता हूँ
तुम्हारा प्यार
हृदय का रस है
जिसका स्वाद
मुझे रसमय
कर देता है
तुम्हारा प्यार
आंखों की लालिमा है
जो एक क्षण भी
दूर नहीं होती
तुम्हारा प्यार
देहरी पर जलता
दीया है/जो..
बाहर-भीतर को
आलोकित करता है
तुम्हारा प्यार
जीवन का सरसतम
गीत है
जो अर्न्तध्वनित
होता रहता है।

-दुर्गाप्रसाद झाला

प्रसंगवश

नेपाल : बालेंदु शाह के सामने अब समस्याओं का पहाड़

अरविंद मोहन

नेपाल के चुनाव में साफ़ जनादेश के बाद अब नई सरकार के सामने बड़ी चुनौतियाँ हैं। बालेन शाह के नेतृत्व में गठित होने वाली सरकार के सामने आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और प्रशासनिक सुधार जैसे बड़े सवाल खड़े हैं।

नेपाल चुनाव और उसके नतीजों की व्याख्या कई तरह से की जा रही है। लेकिन चुनाव की प्रक्रिया के दौरान वहां जो कुछ दिखा उसकी चर्चा कम हुई। चुनाव घोषणा होते ही हर बड़े दल में उठापटक हुई और कई टूट-फूट तथा विलय भी देखने में आये। कई दलों ने अपने 'आराध्य' का नाम लेना पाप समझा तो नेपाली कांग्रेस ने नेपाल के जेन-जी आंदोलन और मुख्य ताकत बनाकर उभर रही राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को देखते हुए नया नेता चुना। तब भी पार्टी चारों खाने चित्त हुई। हर दल ने नौजवानों को आगे करने का प्रयास जरूर किया लेकिन स्थापित पुराना नेतृत्व नतीजों के पहले मैदान छोड़ने को तैयार न था।

जिस समानुपातिक प्रणाली से नेपाल संसद का एक बड़ा हिस्सा भरने की विलक्षण व्यवस्था की गई है, उसके लिए पार्टियों के नामांकन की सूची चुनाव उम्मीदवार चुनने से पहले बनी। और उसे बनाने के क्रम में ही असली झगड़े हुए और आप पाएंगे कि इतने साफ़ जनादेश के बावजूद जब इस व्यवस्था वाले सांसद आएंगे तो काफ़ी पिटे-पिटाए चेहरे दिखने में आएंगे। नेपाल कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई पार्ट दो शुरू होगी और संभव है कि बुरी तरह पिटकर कम्युनिस्ट पार्टियां भी एकजुट होने की कोशिश करें।

लेकिन नेपाल के लोगों ने जितना साफ़ जनादेश दिया है उसे समझने की ज़रूरत है और वह पूरी पुरानी राजनीति को लगभग सीधे नकारने जैसा है। इतना कहने में हर्ज नहीं है कि नेपाली मतदाता ने सारे 'वादों' अर्थात् विचारधारा का नाम लेकर राजनैतिक नौटंकी करने वालों को ठुकराया है। इसमें कम्युनिस्ट खेमे के दल तो हैं ही, दक्षिणपंथी और राजा समर्थक दल भी हैं।

एक पार्टी तो सीधे राजतंत्र की वापसी के नाम पर इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिस्सा ले रही थी। एक सीधे चीन समर्थक पार्टी थी। पर ज्यादा दिलचस्प मामला मधेश और पहाड़ या किसी जाति और क्षेत्र का नाम लेकर राजनीति करने वालों की दुर्गति भी रही। खुद बालेन शाह के मैथिली बयान या मधेशी होने का सवाल भी उठाया गया, लेकिन लगता नहीं कि मतदाता इन बातों से किसी भी तरह प्रभावित हुए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को दो तिहाई बहुमत का मतलब बहुत बड़ा है और वह नए कानून बनाने से लेकर इस पर्वतीय राष्ट्र की किस्मत बनाने-बिगाड़ने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। पर उसकी अपनी राजनीति भी है और प्रधानमंत्री बनने जा रहे बालेंदु उर्फ बालेन शाह और पार्टी अध्यक्ष रबी लामिछाने के बीच भी दोस्ती चुनाव के पहले ही हुई है। लामिछाने के खिलाफ कई गंभीर आरोप भी हैं।

35 साल के बालेंदु शाह ने अभी तक पर्याप्त समझदारी दिखाई है लेकिन काठमांडू शहर के शासन और नेपाल के शासन में फर्क है। उम्मीद करनी चाहिए कि उनका उत्साह और नई ऊर्जा इस जवाबदेही को बहुत बढ़िया ढंग से पूरा करने में मदद देगी। चुनावी वायदों का पिटारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन आँख से दिखती मुश्किलों का पहाड़ वास्तविक पहाड़ों से कम ऊँचा नहीं है। बालेंदु शाह के साथ किसी वाद का तमगा नहीं है, न ही उन्होंने इस तरह के 'फॉर्मूले' वाले ज़्यादा वायदे किए हैं। लेकिन वे विचारधारा से मुक्त होंगे और स्वतंत्र पार्टी का मतलब किसी क़िस्म की मूल्यगत निष्ठा से स्वतंत्र होना नहीं है।

बेरोगजारी, गरीबी, प्राकृतिक संसाधनों का कुप्रबंध या लूट, भारत और चीन जैसे दो बड़े पड़ोसी देशों के बीच संतुलन साधते हुए आगे बढ़ने की चुनौती और लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही दिखी कमजोरियों को दुरुस्त करने का काम इतना बड़ा है कि इन पड़ोसियों से किसी क़िस्म की होड़ लेने या दाँव-पेंच दिखाने की फ़ुर्सत नहीं होगी।

अभी तक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुने गए अधिकांश सरकारों ने नेपाल की खास भौगोलिक अवस्थिति का लाभ अपने स्वार्थ साधने में किया। इस बार नेपाली राजनीति के तीन सूरमा, के. पी. ओली, शेर बहादुर देउबा और प्रचंड एकदम हाशिये पर आ गए हैं। देउबा को तो उनकी पार्टी नेपाली कांग्रेस के नए नेताओं ने ही घर बैठा दिया तो ओली की बुरी पराजय हुई है। प्रचंड जरूर चुनाव जीते हैं लेकिन उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर भी नहीं रह पाई। यह जगह गिरते-पड़ते नेपाल कांग्रेस को ही मिली है। फिर बाबूराम भट्टराई जैसे पूर्व सहयोगी के अलग दल बनाने से भी प्रचंड की पार्टी कमजोर हुई है। संभव है सारी कम्युनिस्ट पार्टियां फिर से एकजुटता का स्वर बुलंद करें लेकिन दुनिया में साम्यवाद की हालत और नेपाल में कम्युनिस्ट नेताओं द्वारा सत्ता संभालने का बुरा अनुभव लोगों को उन पर फिर विश्वास का मौका देगा, यह कहना जल्दबाजी होगी। गगन थापा और शेर बहादुर देउबा की लड़ाई से नेपाल कांग्रेस बंटी पड़ी है लेकिन जब समानुपातिक प्रणाली से सीटें भरने का अवसर आएगा तब देउबा फिर ताकतवर होंगे क्योंकि चुनाव आयोग को नाम भेजने का काम उनके समय ही हुआ है। अब चुनावी धुलाई के बाद जल्दी से राजशाही समर्थक पार्टी या अनेक नामधारी लेकिन अलग-अलग जातीय प्रभाव वाले मधेशी दलों में भी कितना टिक पाएंगे यह देखने की चीज होगी।

ऐसे बड़े और साफ़ जनादेश के बाद बालेंदु शाह के लिए तात्कालिक राजनैतिक चुनौतियां तो कम होंगी लेकिन उनको वापस लौटने में देर नहीं लगती। पर जिस तरह लोगों ने पुरानी राजनीति को ठुकराया है वैसा ही बदलाव एक अन्य मामले में दिखता है। के. पी. ओली और उनकी पार्टी की हार उनकी मौकापरस्त राजनीति के साथ नेपाल की राजनीति में चीनी दखल की कूटनीति को नकारना भी है। सौभाग्य से इस बार भारत की तरफ से या किसी भारतीय दल की तरफ से कोई ज्यादा नुकसानदेह बयानबाजी नहीं की गई।

बालेन शाह का एकाध भारत विरोधी बयान चलाने की कोशिश हुई तो यह तथ्य आने में देर नहीं हुई कि वह किसी और चीज/गलती की प्रतिक्रिया थी। नए आदमी के लिए राजनयन भी कोरे पन्ने के साथ शुरू हो तो अच्छा रहता है। लेकिन मुख्य मसला देसी ही रहने वाला है क्योंकि नेपाल के पास अपनी समस्याओं की कमी नहीं है। और समस्याओं में असली समस्या नेताओं और जिम्मेवार लोगों का भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद की रही है। लोकतंत्र आने के बाद से गिनती के नेताओं का आचरण ही शक-शुबहे से ऊपर रहा है और उनकी चलने नहीं दी गई। इस बार जनता ने ऐसे सारे झमेले किनारे करके बालेंदु शाह को सत्ता सौंपी है। सितंबर में हुई बगावत अपनी समस्याओं के साथ नेताओं के आचरण के खिलाफ थी, इस बात को शाह से बढ़िया कौन जानता है।

(सत्य हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

कोकराझार में 4,570 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन

● गुवाहाटी में पीएम बोले-दशकों तक बोडोलैंड का एक क्षेत्र विश्वासघात का साक्षी रहा है

गुवाहाटी (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से दो दिन के असम दौरे पर हैं। दोपहर करीब 1.30 बजे वे गुवाहाटी पहुंचे। पीएम गुवाहाटी के अलावा आज कोकराझार और सिलचर का दौरा करने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्होंने कोकराझार में प्रोजेक्ट्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। पीएम ने लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा- दशकों तक बोडोलैंड का एक क्षेत्र विश्वासघात का साक्षी रहा है। बोडोलैंड के अनेक वीडियो को कांग्रेस ने झूठे सपनों में उलझाए रखा। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दिखाने के लिए कागजी समझौते किए। आपने कांग्रेस को खदेड़ा और एनडीए को मौका दिया तो हमने समझदारी से फैसले लिए। इसके बाद पीएम गुवाहाटी से सिलचर जाएंगे।

● कांग्रेस एक वादे के साथ चार झूठ गिफ्ट में देती है- कांग्रेस झूठे वादों की दुकान है। एक वादे के साथ चार झूठ गिफ्ट में देती है। वहीं, आपके सामने बीजेपी का सफल मॉडल है। 2003 में जब दिल्ली में एनडीए सरकार थी। अटल जी के नेतृत्व में सच्चाई और ईमानदारी से काम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एनडीए की दोहरी इंजन सरकार असम की विरासत के संरक्षण और उसके तीव्र विकास दोनों के लिए लगातार काम कर रही है। कोकराझार सहित इस पूरे क्षेत्र ने पिछले कुछ दशकों में भारी कठिनाइयों का सामना किया है। इसे भारी नुकसान उठाना पड़ा है। आज बोडोलैंड शांति और विकास के पथ पर अग्रसर है।

● भागवत की मौजूदगी में संघ की समीक्षा, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन पहली कतार में बैठे

आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हरियाणा में शुरू

पानीपत (एजेंसी)। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा शुक्रवार को हरियाणा के पानीपत में शुरू हो गई। यह सभा संघ की सर्वोच्च निर्णायक इकाई है और पानीपत में इसकी ये मीटिंग 3 दिन चलेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत इसके लिए सात दिन पहले ही पानीपत में बने संघ के सेंटर पहुंच गए और तब से यहीं मौजूद हैं। संघ को नया रूप देने की चर्चाओं के बीच यह सभा बेहद अहम मानी जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन भी तीनों दिन यहां रहेंगे। पहले दिन मंच पर संघ प्रमुख मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ही बैठे। नबीन को पहली कतार में कुर्सी पर जगह मिली।

● **पहले दिन शताब्दी वर्ष के कामों पर चर्चा**- अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि पहले दिन आरएसएस के शताब्दी वर्ष में हुए कामों पर चर्चा होगी। दूसरे दिन आरएसएस के प्रकल्पों में आई चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही अगले एक साल में किए जाने वाले कामों की रूपरेखा तय होगी। आखिरी दिन यानी 15 मार्च को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संबोधन होगा। उसके बाद दत्तात्रेय होसबाले सभा में हुए निर्णयों और पारित प्रस्तावों की आधिकारिक जानकारी मीडिया में साझा करेंगे। आरएसएस में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा एक तरह से निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी इकाई है।

●ग्वालियर जिले को दी 122 करोड़ रुपये के 54 विकास कार्यों की सौगात ● लाड़ली बहना योजना ने बहनों को बनाया स्वावलंबी,लाड़ली बहना योजना की 34वीं किश्त बहनों के खातों में डाली

डबल इंजन की सरकार में बहनों को मिल रही हैं डबल खुशियां : मुख्यमंत्री

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश की बहनें आत्मनिर्भरता एवं स्वावलम्बन के मामले में पूरे देश के लिए उदाहरण बन रही हैं। प्रदेश के 5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों से जुड़कर करीब 65 लाख बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हुई हैं। आज प्रदेश में 12 लाख से अधिक लखपति दीदियां कार्यरत हैं। हम महिला उद्यमियों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारी बहनें अब फैक्ट्रियों और उद्योगों का नेतृत्व कर रही हैं। प्रदेश के 47 प्रतिशत नए स्टार्ट-अप का नेतृत्व अब हमारी बहनों के हाथों में है। हम सभी बहनों के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड में कार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इसलिए यहां की बहनों को लाड़ली लक्ष्मी और लाड़ली बहना योजना के रूप में डबल खुशियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को ग्वालियर जिले के शबरी माता मंदिर परिसर, घाटीगांव में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में लाड़ली बहनों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत प्रत्येक कठिन परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। उन्होंने वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा है। इसमें प्रदेश की बहन-बेटियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नवरात्रि से पहले आज बहनों को 1500 रुपए की सौगात मिल रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लाड़ली बहना योजना में बहनों को योजना की 34वीं किश्त प्रदेश की 1 करोड़ 25 लाख 27 हजार से अधिक बहनों के खाते में 1 हजार 836 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की। इनमें ग्वालियर जिले की 3 लाख 16 हजार से अधिक लाड़ली बहनें भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अब प्रदेश की हर लाड़ली बहनों के खाते में हर महीने 1500 रुपये भेजे जा रहे हैं। लाड़ली बहन योजना में अब तक 52 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि बहनों को दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सभी लाड़ली बहनों से अपील करते हुए कहा कि वे हर महीने मिलने वाली इस राशि से अपनी बेहतरी के लिए कोई भी रुचिकर काम-धंधा शुरु करें और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में योगदान दें।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर जिले को 121 करोड़ 95 लाख रुपये की लागत वाले 54 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने सिंगल क्लिक से लगभग 60 करोड़ रुपये की लागत के 35 विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लगभग 62 करोड़ रुपये की लागत वाले 19 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 39 करोड़ 86 लाख रुपये की लागत से कुलैथ घाटीगांव में शासकीय सांदीपनि विद्यालय के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भी शामिल है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 2 महीने बाद लाड़ली बहना योजना के 3 साल पूरे हो जाएंगे। इन 3 सालों में प्रदेश की बहनों की जिन्दगी जिस तरह से बदली है, वह भूतो न भविष्यति है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जनवरी 2024 से फरवरी 2026 तक 42 हजार 308 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि बहनों के खाते में भेजी गई है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना से प्रदेश की बहनें अब आत्म-निर्भर बन गई हैं। अब वे मजबूर नहीं, मजबूत हो गई हैं।

प्रमुख घोषणाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भितरवार विधानसभा क्षेत्र में आरोन-पटई उद्वहन सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि 120 करोड़ रुपए की यह परियोजना क्षेत्र के किसानों का जीवन खुशहाल कर देगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर घाटीगांव सहित चिनौर और करैया में भी सांदीपनि विद्यालय खोले जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भितरवार पीएचसी का उन्नयन कर सिविल अस्पताल बनाया जायेगा। घाटीगांव के उप स्वास्थ्य केंद्र का भी उन्नयन कराएंगे। भितरवार और घाटीगांव में युवाओं के कौशल विकास के लिए आईटीआई केंद्र की स्थापना करेंगे। घाटीगांव में शबरी माता के भव्य मंदिर और शबरी धाम निर्माण के लिए भूमि का सर्वे कराया जाएगा। भगवान देवनारायण का भी धाम बनाया जायेगा। संस्कृति विभाग के माध्यम से देवनारायण मंदिर में हर साल सांस्कृतिक आयोजन कराये जायेंगे।

अब दुनिया के सभी देश रूस से खरीद सकेंगे तेल

● अमेरिका ने ईरान युद्ध के कारण दी है 30 दिन की मोहलत ● ईरान ने क्रूड ऑयल 200 डॉलर पहुंचने की चेतावनी दी थी

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका-इजराइल की ईरान से चल रही जंग की वजह से दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 100 डॉलर के पार चली गई हैं। इसे काबू में करने के लिए ट्रम्प प्रशासन ने दूसरे देशों को भी रूस से तेल खरीदने की अस्थाई मंजूरी दे दी है। रूस के कई ऑयल टैंकर समुद्र में फंसे हैं। इससे पहले अमेरिका ने भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए प्रतिबंधों में ढील देने की बात कही थी।

● **सिर्फ समुद्र में फंसे जहाजों से तेल खरीदने की मंजूरी**- मेरिकी ट्रेजरी विभाग (वित्त मंत्रालय) ने गुरुवार को एक लाइसेंस जारी किया। इसके तहत उन रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिलीवरी और बिक्री की जा सकती है, जो 12 मार्च की रात 12:01 बजे से पहले जहाजों पर लोड हो चुके थे।

यह छूट सिर्फ 11 अप्रैल तक के लिए दी गई है। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने बताया कि इसका मकसद दुनियाभर में तेल की सप्लाई बढ़ाना है, ताकि बढ़ती कीमतों पर लगाम लग सके। अमेरिका के ट्रेजरी मंत्री स्कॉट बेसेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि राष्ट्रपति ट्रम्प वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि यह एक शॉर्ट-टर्म फैसला है और इससे रूस को कोई बहुत बड़ा आर्थिक फायदा नहीं होगा। बेसेंट के मुताबिक रूस की कमाई का बड़ा हिस्सा तेल निकालने के वक्त लगने वाले टैक्स से आता है, जबकि यह छूट सिर्फ उस तेल के लिए है, जो पहले से ही ट्रांजिट (रास्ते) में है। होर्मुज रूट से सप्लाई ठप : ईरान और अमेरिका-इजराइल के बीच जंग से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में सप्लाई ठप हो गई है। यहां से दुनिया का करीब 20 फीसदी तेल गुजरता है। भारत जैसे देश अपनी जरूरत का करीब आधा तेल इसी रास्ते से मंगाते हैं।

● **200 डॉलर पहुंच सकता है कच्चा तेल**- पिछले कुछ दिनों में ब्रेंट क्रूड की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई थीं। ईरान ने चेतावनी दी है कि कीमतें 200 डॉलर तक पहुंच सकती है। ऐसे में रूसी तेल बाजार में आने से सप्लाई बढ़ेगी, जिससे कीमतों में गिरावट आएगी। जब फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तो पश्चिमी देशों का मानना था कि युद्ध के लिए पैसा रूस को तेल और गैस बेचकर मिल रहा है। इसी 'फंडिंग' को रोकने के लिए अमेरिका और यूरोप ने रूस से तेल खरीदने पर पाबंदी लगानी शुरू की थी। मिडिल ईस्ट में एनर्जी सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हाल ही में हुए हमलों के बाद फिर से ज्यादा की तेजी आई है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c | न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

इंदौर ■ शनिवार, 14 मार्च 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

आज दोपहर 1.59 बजे क्या खास होने वाला है ?

शकील खान
(फिल्म और कला समीक्षक)

बात पुराने जमाने की है, उन दिनों लोगों को भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत परेशानी होती थी। हर सवाल का एक जवाब होता है और हर परेशानी का एक हल। सो इस परेशानी का हल भी निकलना था, निकला और साल्यूशन के रूप में घोड़ागाड़ीनुमा एक चीज बनाई गई , जिसमें गोल पहिए लगे थे। पहिए बन गए, गाड़ी में लगा भी दिए गए, किन ये पूरी तरह गोल नहीं थे। सो गाड़ी हिचकोले खाने लगी। अंततः एक परफेक्ट गोल पहिया बना लिया गया। लेकिन मुश्किल उसे गोल आकार में ढालना था। खासी मशक्कत के बाद पहिया सही गोल आकार में ढल सका। इसे संभव बनाया एक मिस्ट्री नंबर ने। यह मिस्ट्री नंबर क्या है और इसका 14 मार्च दोपहर 1.59 से क्या संबंध है?

पहिए ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया है। बड़े से बड़े सामान को जब व्हील का सहारा मिलता है, तो उसे मूव करना आसान हो जाता है। पहले भारी सामान को इधर से उधर करना या उसके साथ सफर करना बहुत मुश्किल हुआ करता था । व्हील ने इसे आसान बना दिया है। लेकिन व्हील ठीक से गोलाकार नहीं है तब उसे चलाना या ढकेलना बहुत मुश्किल होता है। एक उदाहरण के लिए व्हील अगर अच्छे नहीं हुए तो सूटकेस को धकेलना मुश्किल हो जाता है। यानी सही चलने के लिए व्हील को आकार में सही और सटीक होना बहुत जरूरी है।

उलझन सुलझाने के प्रयास किए गए और अंततः एक परफेक्ट गोल पहिया बना लिया गया। अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ी तब जाकर गोल पहिया बना और 22/7 अनुपात वाला मेजरमेंट सामने आया। इसे 'पाई' के नाम से पुकारा गया और इसे मिस्ट्री नंबर का खिताब भी दिया गया। इस तरह 'पाई' की गणित में एंट्री हुई साथ ही हमारी जिंदगी में भी।

आपको स्कूल की याद है। परकार में पेंसिल लगाकर हम उसे लाईन के ठीक सेंटर में रखकर उसे घुमाते थे और सर्किल बनाया करते थे एक बार फिर उसे दोहराएं, सात सेंटीमीटर की एक लाइन खींचकर इसके चारों तरफ एक परफेक्ट गोलाकार सर्किल बनाएं। सात सेंटीमीटर की जो ये लाइन खींची है उसे डायमीटर (डी) या व्यास कहते हैं। इस सर्किल की गोलाई को परिधि यानी सरकम्फ्रेंस (सी) कहते हैं। परिधि को नापें तो पाएंगे कि यह 22 सेंटीमीटर की है। इनका अनुपात हुआ 22 बटा 7। सर्किल आप चाहे जितना छोटा बनाएं या जितना भी बड़ा, सरकम्फ्रेंस और डायमीटर का अनुपात हमेशा समान ही रहेगा - 22 /7 ही रहेगा। इस अनुपात को ही ''पाई'' (p) से दर्शाया जाता है। पाई का मान हमेशा कांस्टेंट रहता है। अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर कर दें तो सरकम्फ्रेंस 44 सेंटीमीटर का ही निकलेगा। और अनुपात होगा 44/14 अर्थात् 22/7 । कोई भी नाप लें पाई अनुपात हमेशा समान ही रहेगा।

पाई (p) शब्द आया कहां से ? यह ग्रीक अल्फाबेट का सोलहवां अक्षर है, दिलचस्प है कि पाई का पहला शब्द 'पी' भी अंग्रेजी वर्णमाला का सोलहवां अक्षर ही है। अहम सवाल 'पाई' को मिस्ट्री नंबर क्यों कहा जाता है। असल में पाई का सही मान आज तक निकाला ही नहीं जा सका है। पाई बराबर 22/7 होता है यह हम जानते हैं लेकिन पाई का यह मान ''22/7 = 3.14159' पूरी तरह एक्युरेट नहीं है। जब हम 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.1428571429 आएगा। लेकिन बता दें कि 3.14159 सर्वत्र मान्य है। पाई चूंकि अपरिमेय यानि इरेशनल नंबर है इसलिए ऐसा होता है।

बहरहाल, पाई की वेल्यू हमारे लिए बहुत उपयोगी है खासतौर पर स्पेश मिशन के लिए तो बहुत ही ज्यादा। इसीलिए पाई नासा जैसी संस्थाओं के लिए एक महत्वपूर्ण नंबर है। नासा इसकी केवल 40 डिजिट का ही इस्तेमाल करता है। इसकी एक्यूरेट वैल्यू और एप्राक्सीमेट वैल्यू में माईक्रोमिलियन का अंतर रहता है, ये एरर इतनी कम कि इसे आसानी से इग्नोर किया जा सकता है, किया जा भी रहा है।

ये भी बता दें, इसकी परफेक्ट वैल्यू निकालने में अनेक गणितज्ञों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ट्रिलियंस ऑफ डिज़िट के केलक्यूलेशन के बाद सुपर कम्प्यूटर ने भी इसके आगे घुटने टेक दिए। इस कोशिश का अलग प्रतिफल यह निकला कि सुपर कम्प्यूटर की केलकुलेशन ने ये बता दिया कि जो कम्प्यूटर जितना ज्यादा पाई की वैल्यू निकालेगा, जितनी ज्यादा डिजिट तक वैल्यू निकालेगा उस कम्प्युटर की कम्प्यूटिंग पॉवर उतनी अधिक मानी जाएगी। इस तरह पाई का मान निकलवाकर कम्प्यूटर की कम्प्यूटिंग औकात नापने का जरिया तो खोज लिया ही गया है।

पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है वो भी ठीक दोपहर 1.59 बजे। तमाम तरह के दिन एक खास दिनांक को मनाए जाते हैं ये तो हमें पता है लेकिन एक तारीख विशेष पर खास समय पर कोई दिन मनाया जाए ये पाई डे के साथ ही होता है। जानना दिलचस्प होगा कि 14 मार्च और 1.59 का पाई डे से क्या संबंध है।

पाई डे के साथ एक दिलचस्प संयोग भी जुड़ा है। 14 मार्च यानि पाई डे से दो महान वैज्ञानिक रिलेटेड हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइंस्टाइन और कुछ बरस पहले दुनिया से विदा हुए स्टीफन विलयिम हॉकिंग। संयोग से दोनों में से एक का जन्म और दूसरे का मृत्यु दिनांक एक ही है। आइंस्टाइन का बर्थडे 14 मार्च (1879) को और स्टीफन हॉकिंग ने 14 मार्च (2018) को इस फानी दुनिया को अलविदा कहा।

लेकिन जरूरी सवाल का जवाब अभी बाकी है। पाई डे 14 मार्च को दोपहर एक बजकर उनसठ मिनिट (1.59) बजे क्यों मनाया जाता है? इसका रहस्य पाई की वैल्यू में छिपा हुआ है। पाई की वैल्यू है - 3.14159 । यहां तीन यानि तीसरा महीना मार्च को रिप्रजेंट करता है। दशमलव के बाद है 14 इससे बनी तारीख। बचा 159 इससे बना समय 1 बजकर 59 मिनिट और इस तरह बन गया 'पाई डे'।

संक्षिप्त समाचार

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को सता रहा हॉर्स ट्रेडिंग का डर

● ओडिशा से 8 विधायक बेंगलुरु भेजे हरियाणा में लंच पर बुलाया

भुवनेश्वर (एजेंसी)। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। इसके चलते उसने ओडिशा और हरियाणा में अपने सभी विधायकों को बचाने के लिए रिजॉर्ट में रखने का फैसला किया है। ओडिशा कांग्रेस के 8 विधायकों को बेंगलुरु भेजा गया है। जो दक्षिण बेंगलुरु के वंडरला रिजॉर्ट में ठहरे हैं। 6 विधायक विधानसभा के बजट सत्र में

शामिल होने के लिए भुवनेश्वर में ही मौजूद हैं। शनिवार सुबह तक चार और एमएलए बेंगलुरु पहुंच सकते हैं। इससे पहले चीफ व्हिप राजेन एक्का समेत 6 विधायक गुरुवार रात परिवार समेत बेंगलुरु पहुंच गए हैं। उधर, हरियाणा में 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं। चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों को लंच पर बुलाया गया। इन विधायकों को 5 जोड़ी कपड़े साथ लाने कहा गया है।

बिहार में निशांत को सीएम बनाने की उठ रही है मांग

● नीतिश के करीबी मंत्री ने खोल दिया सबसे बड़ा पत्ता

पटना (एजेंसी)। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने जदयू नेता निशांत कुमार के सीएम बनने की अटकलों के बारे में कहा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला एनडीए का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। पटना में मीडिया से मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया कि अभी मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और इस पर आखिरी फैसला एनडीए के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। मंत्री श्रवण कुमार का यह बयान उस वक्त आया है जब सीएम नीतिश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले के बाद उनके बेटे की जदयू में एंट्री हुई है और बिहार में अगला सीएम उन्हें बनाने की मांग चल रही है। जदयू के कई विधायक निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि निशांत कुमार को सीएम बनाने की मांग स्वाभाविक है। उनके समर्थक चाहते हैं कि वे सीएम बनें, वे अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन सीएम बनने को लेकर फैसले एनडीए के बड़े नेता करेंगे। जाहिर है कि श्रवण कुमार ने कार्यकर्ताओं और जेडीयू के कुछ नेताओं के बहाने निशांत कुमार के सीएम बनाने की डिमांड पर एक तरह से मुहर लगा दी है।

भारत में बन रहे हैं 6,600 मेगावाट के परमाणु संयंत्र

● वर्ष 2031-32 तक बदल जाएगी देश की ऊर्जा सूरत

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिजली मंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को लोकसभा को बताया कि देश में लगभग 6,600 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता के संयंत्र निर्माणाधीन है। उन्होंने यह भी कहा कि 12,723.50 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। 4,274 मेगावाट की जलविद्युत परियोजनाएं योजनाओं के विभिन्न चरणों में हैं और 2031-32 तक पूरा होने का लक्ष्य है। मनोहर लाल ने लिखित उत्तर में कहा कि 6,600 मेगावाट क्षमता के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण 2029-30 तक पूरा होने का लक्ष्य है। सात हजार मेगावाट क्षमता के अन्य परमाणु संयंत्र योजना और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में है। भारत की वर्तमान परमाणु क्षमता 8,780 मेगावाट से अधिक है। 11,620 मेगावाट/69,720 मेगावाट-घंटे की पंप स्टोरेज परियोजनाएं (पीएसपी) निर्माणाधीन हैं। 6,580 मेगावाट/39,480 मेगावाट घंटे की क्षमता वाली पीएसपी को मंजूरी मिल चुकी है। 9,653.94 मेगावाट/ 26,729.32 मेगावाट-घंटे की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएस) का निर्माण कार्य चल रहा है।

पीरियड्स में पेड लीव की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी खारिज

● सीजेआई बोले-कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को देशभर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं को पीरियड्स में पेड लीव देने की मांग वाली याचिका खारिज हो गई। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि ऐसी याचिकाएं अनजाने में महिलाओं के बारे में बनी रूढ़ियों को और मजबूत कर सकती हैं। यह कानून बनाया तो महिलाओं को कोई काम नहीं देगा, उनका करियर खत्म हो जाएगा। सीजेआई ने कहा- ये याचिकाएं डर पैदा करने के लिए, महिलाओं को हीन दिखाने के लिए, यह जताने के लिए दायर की जाती हैं कि पीरियड्स उनके साथ होने वाली कोई बुरी चीज है। यह उनका पॉजिटिव राइट है, लेकिन उस नियोक्ता के बारे में सोचिए, जिसे पेड लीव देनी होगी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान मेंस्ट्रुअल लीव को अनिवार्य बनाने के संभावित सामाजिक परिणामों के बारे में चिंता जाहिर की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अधिकार क्षेत्र पर भी सवाल उठाया और कहा कि इस मामले को लेकर खुद कोई महिला कोर्ट में नहीं आई है।

● 'ये सड़क मुस्लिमों के लिए नहीं', लिखने वाली युवतियां अरेस्ट

सहारनपुर में बोलीं-सनातन के लिए 10 बार जेल जाने को तैयार

सहारनपुर (एजेंसी)। सहारनपुर में सांप्रदायिक नारे लिखने के आरोप में पुलिस ने दो युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि तीनों ने दिल्ली-देहरादून नेशनल हाईवे पर यह सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है जैसे स्लोगन लिखे थे। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को तीनों को जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के बाद एक युवती ने कहा कि वे सनातन के लिए एक बार नहीं, बल्कि 10 बार भी जेल जाने को तैयार हैं। तीनों आरोपी देहरादून के रहने वाले हैं और खुद को हिंदू रक्षा दल का कार्यकर्ता बताते हैं। उधर, हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने भी मामले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि ये नारे उनकी महिला कार्यकर्ताओं ने लिखे थे। पूरा मामला सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक,26 फरवरी की देर शाम तीनों आरोपी नेशनल हाईवे-72ए (एलिवेटेड रोड) पर पहुंचे। वहां उन्होंने सड़क किनारे बने सीमेंटेड ब्लॉक और शेड पर स्प्रे पेंट से नारे लिखना शुरू कर दिया।

देश भर में सिलेंडर के लिए संग्राम

● पंजाब में सिलेंडर लेकर सड़क पर भागते दिखी जनता ● 2 हजार का कॉमर्शियल सिलेंडर 4 हजार में बिक रहा

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिका-इजराइल की ईरान से जंग की वजह से देशभर में एलपीजी की किल्लत हो गई है। गैस एजेंसियों के बाहर लम्बी लाइनें हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। कई जगहों पर 2 हजार का कॉमर्शियल सिलेंडर 4 हजार में बिक रहा है। वहीं पंजाब में लोग सिलेंडर लेकर भागते नजर आए। केरल में करीब 40 फीसदी रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पर है। उधर, दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी सप्लाई की बिगड़ी स्थिति को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। विरोध जताने के लिए मिट्टी के चूल्हे लेकर आए थे।

एमपी की ऑनलाइन बुकिंग ठप, वेटिंग 7-8 दिन बढ़ी

मध्य प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग लगभग ठप है। सर्वर डाउन होने से भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में लोग सिलेंडर की बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वेटिंग 7 से 8 दिन तक पहुंच गई है। गैस एजेंसियों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। इधर गैस की किल्लत के बीच इंडक्शन की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। भोपाल में इसकी बिक्री 7 गुना तक बढ़ गई है। वहीं 50 हजार होटल-रेस्टॉरेंट में गैस खत्म होने के कगार पर है।

● राजस्थान में गैस सप्लाई ठप, सिलेंडर की शवयात्रा निकाली- होटल-रेस्टोरेंट में गैस का स्टॉक खत्म होने से बिजनेस ठप होने लगे हैं। कई जगह ताले भी लटकने लगे हैं। वहीं कोटा समेत कई शहरों में हॉस्टल मेस और ढाबों में मजबूरी में लकड़ी, कोयले और इलेक्ट्रिक चूल्हों पर खाना बनाया जा रहा है। कई शहरों में एजेंसियों पर सुबह 5 बजे से ही लंबी लाइनें लग रही हैं और सिलेंडर न मिलने पर लोगों की पुलिस से झड़प तक हो रही है। इस संकट के बीच सिलेंडर की कालाबाजारी भी हो रही है, जिसके विरोध में कांग्रेस ने जयपुर में सिलेंडर की शवयात्रा निकाली।

● उत्तर प्रदेश में चूड़ी से लेकर पेठा फैक्ट्रियां तक बंद- यूपी में फैक्ट्रियों को गैस सप्लाई नहीं हो रही है। इसका असर पॉटरी, चूड़ी से लेकर पेठा फैक्ट्रियों तक पड़ रहा। बुलंदशहर में एशिया के सबसे बड़े पॉटरी उद्योग पर पड़ा है। यहां 300-325 यूनिट में से 95 फीसदी पॉटरी यूनिट बंद हैं। 30 हजार से ज्यादा वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। यही हाल फिरोजाबाद में बनने वाली चूड़ियों और आगरा की पेठा फैक्ट्रियों का है। गैस की सप्लाई नहीं मिलने से भट्ठियां बंद हैं। 55 बड़ी फैक्ट्रियों में से 40 बंद हो चुकी हैं।

महाराष्ट्र में हर जिले में बनेगा कंट्रोल रूम और कमेटी

राज्य में एलपीजी की बिना रुकावट सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम और कमेटियों का गठन किया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अधिकारियों को गैस वितरण व्यवस्था पर पैनी नजर रखने को कहा है। वहीं कई ग्राहकों ने ऑनलाइन और फोन पर सिलेंडर बुक किए हैं, लेकिन उन्हें समय पर डिलीवरी नहीं मिल रही है।

एलपीजी संकट पर लोकसभा में विपक्ष ने की नारेबाजी

विपक्ष ने दोनों सदनों में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का नोटिस दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। लोकसभा में शुक्रवार को प्रश्नकाल की शुरुआत के साथ ही विपक्ष ने हंगामा किया। राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने 8 निलंबित सांसदों की वापसी की मांग की। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा- सदन की मेजों पर चढ़ोगे तो यही ऐक्शन होगा। संसद की प्रतिष्ठा बनाने की जिम्मेदारी सभी की है। इसके बाद लोकसभा पहले 12 बजे तक और दूसरी बार 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे शुरू हुई कार्यवाही भी केवल 1 घंटा चली। इसके बाद लोकसभा को 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले विपक्षी दलों ने संसद परिसर में प्लेकार्ड दिखाकर एलपीजी संकट पर प्रदर्शन किया। राज्यसभा भी कल तक के लिए स्थगित की गई है।

तेहरान में अलविदा जुमा पर हुआ जबरदस्त धमाका

● इजरायल के खिलाफ जुटे थे हजारों, मच गई अफरातफरी

तेहरान (एजेंसी)। ईरान की राजधानी तेहरान में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच धमाका हुआ है। यह ब्लास्ट उस वक्त हुआ, जब तेहरान के फिरदौसी चौक पर हजारों लोग ईरान और अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन करने जुटे थे। आज ईद से पहले का आखिरी जुमा है, जिसे अलविदा जुमा कहा जाता है। इस कारण भी प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस दौरान जब धमाका हुआ तो दहशत फैल गई और लोग मौके से भागते नजर आए। इस धमाके के पीछे ईरानी एजेंसियों को इजरायल का हाथ होने का शक है। अब तक धमाके की वजह सामने नहीं आई है, लेकिन इजरायल ने हमलों की चेतावनी दी थी। ऐसे में माना जा रहा है कि यह धमाका भी इजरायल ने ही किया है। यह धमाका ऐसे वक्त में हुआ, जब ईरान में अलविदा जुमा मनाया जा रहा है। ईद से पहले के आखिरी जुमा के दिन खूब भीड़ जुटी थी।

क्रॉस वोटिंग या फिर 'दक्षिणा' के भरोसे हैं उपेंद्र कुशवाहा

● बिहार में होगा खेला, अब भी तस्वीर नजर आ रही धुंधली

पटना (एजेंसी)। बिहार से राज्यसभा की पांच सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होगा। चूंकि पांच सीटों पर छह उम्मीदवार हैं इसलिए मतदान होगा। मतदान होगा तो एनडीए के पांचवें उम्मीदवार के लिए 3 वोट कम पड़ जाएंगे। एनडीए का यह पांचवां उम्मीदवार तभी जीतेगा जब 3 विधायक क्रॉस वोटिंग करें या फिर पांच या इससे अधिक विधायक मतदान में गैरहाजिर हो जाएं। छठे उम्मीदवार राजद के अमरेन्द्रधारी सिंह तभी जीत सकते हैं जब एआईएमआईएम के पांच और बसपा के एक विधायक उन्हें वोट दें। इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं है। इसलिए मतदान के दिन इधर से उधर होने की संभावना है।

● भोज-भात का दौर और 'दक्षिणा'- अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में गुरुवार से ही भोज-भात दौर चल रहा है। 14 मार्च को उपेन्द्र कुशवाहा के आवास पर भोजन का प्रबंध है। इसके बाद 15 मार्च को संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के यहां भोज है। डिनर डिप्लोमेसी में बहुत कुछ तय होता है। अगर एनडीए की तरफ से भोजन के साथ-साथ कल्याण करने वाले पुरोहितों को 'उत्तम दक्षिणा' देने की भी प्रबंध हो जाए तो पांचवां प्रत्याशी जरूर 'भवसागर' पार कर जाएगा। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा। विधायकी कुर्बान कर भी कल्याण करने वालों की कमी नहीं है। 2010 में राजद और कांग्रेस के विधायक पार्टी लाइन को दरकिनार करते हुए वोटिंग कर चुके हैं।

66 सिलेंडर, मोटरसाइकिल व उपकरण जब्त

इंदौर। शहर में गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण और कालाबाजारी के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए न्यू लोहा मंडी क्षेत्र में एक अवैध गैस गोदाम का भंडाफोड़ किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई कर 66 गैस सिलेंडर सहित कई उपकरण जब्त किए और भंडारण स्थल को सील कर दिया। गठित दल ने गुरुवार सुबह करीब 6 बजे कार्रवाई की। टीम ने हरिओम गुप्ता के वैध गोदाम पर छापा मारते हुए 24 व्यावसायिक और 42 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए। इसके अलावा गैस रिफिलिंग में उपयोग होने वाली तीन इलेक्ट्रिक मोटर और दो तौल कांटे भी मौके से जब्त किए गए। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि सिलेंडरों की ढुलाई और रीफिलिंग के काम में एक बुलेट मोटरसाइकिल का उपयोग किया जा रहा था, जिसे टीम ने जब्त कर लिया। छापे के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। कार्रवाई के बाद गोदाम में रखे सभी सिलेंडर और उपकरण जब्त कर भंडारण स्थल को सील कर दिया गया है। मामले में आगे की जांच और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

प्री-डिपार्चर डिटेंशन में रतलाम मंडल अव्वल

इंदौर। पश्चिम रेलवे के रतलाम मंडल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चरण में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। फरवरी 2026 में प्री-डिपार्चर डिटेंशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रतलाम मंडल ने भारतीय रेलवे के बड़े मंडलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि से पश्चिम रेलवे को गौरव मिला है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार जिन मंडलों में प्रतिदिन 100 से अधिक मालगाड़ियों के लिए टीए जारी किए जाते हैं, उनमें रतलाम मंडल ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। यह सफलता विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और कुशल कार्यप्रणाली का परिणाम मानी जा रही है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि इस उपलब्धि के पीछे क्रू बुकिंग प्रक्रिया का आधुनिकीकरण प्रमुख कारण रहा है। मंडल में क्रू बुकिंग के लिए 100 प्रतिशत एफओआईएस-सीएमएस (फ्रेट ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम) और क्रू मैनेजमेंट सिस्टम का एकीकरण सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही क्रू लॉबी की नियमित निगरानी व्यवस्था लागू की गई है, जिससे कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पर भेजना और मालगाड़ियों के संचालन में देरी को कम करना संभव हो पाया है।

5वीं-8वीं के छात्रों को जनरल प्रमोशन?

इंदौर। जिले के सरकारी स्कूलों में इस वर्ष कक्षा पांचवीं और आठवीं के छात्रों को अघोषित रूप से जनरल प्रमोशन देने की तैयारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण और अन्य शासकीय कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी लगने के कारण पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हुईं। सूत्रों के अनुसार इस बीच जनगणना जैसे काम भी शुरू हो गए, जिससे शिक्षकों की उपलब्धता और कम हो गई। हालांकि विद्यार्थियों की परीक्षाएं आयोजित की गईं, लेकिन किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाएगा और सभी को अगली कक्षा में भेजने की तैयारी है। छात्रों को अंकसूची भी दी जाएगी, जिसमें उन्हें उत्तीर्ण दर्शाया जाएगा। कॉपियों की जांच राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश पर केंद्रीय समिति द्वारा की जा रही है। इसके लिए शहर के शासकीय बाल विनय मंदिर में कॉपियां जांची जा रही हैं। शिक्षा विभाग के सूत्रों का कहना है कि कोरोना काल की तरह इस बार भी सभी छात्रों को पास करने का फैसला लिया जा सकता है। निजी स्कूल अपने स्तर पर मूल्यांकन करेंगे।

प्रवचन से प्रभावित बालक घर से लापता

इंदौर। शहर के खजराना थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आध्यात्मिक प्रवचनों से प्रभावित होकर 13 वर्षीय एक नाबालिग बालक घर छोड़कर चला गया। घर से जाने से पहले उसने अपने माता-पिता के नाम एक पत्र भी लिखा, जिसमें बताया कि वह अपने 'असली परिवार' के पास जा रहा है और उसे ढूंढने की कोशिश न की जाए। जानकारी के अनुसार घटना खजराना थाना क्षेत्र की श्री कृष्णा विहार कॉलोनी की है। यहां रहने वाला 13 वर्षीय बालक अचानक घर से लापता हो गया। जब परिजनों को वह घर में नहीं मिला तो उन्होंने आसपास उसकी तलाश शुरू की। इसी दौरान घर में एक पत्र मिला, जिसे पढ़कर परिवार के लोग हैरान रह गए। पत्र में बालक ने लिखा कि वह आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अपने असली परिवार के पास जा रहा है। उसने यह भी लिखा कि मम्मी-पापा उसे खोजने की कोशिश न करें, क्योंकि उनके साथ उसका जीवन पूरा हो चुका है। बताया जा रहा है कि घर से निकलते समय वह करीब 500 रुपये भी अपने साथ ले गया। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि ये पैसे उसका एक दोस्त वापस कर देगा। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तुरंत खजराना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर बालक की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है।

'संकल्प से समाधान' अभियान को गति

इंदौर। कलेक्टर के निर्देशन में 'संकल्प से समाधान' अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत विभिन्न विभागों की सेवाओं और योजनाओं से जुड़े आवेदनों के त्वरित निराकरण के लिए लगातार शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अब तक जिले में आयोजित शिविरों में एक लाख 32 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 1 लाख 29 हजार 313 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है, जबकि शेष आवेदनों पर कार्रवाई जारी है। अभियान के तहत 65 सेवाओं और 41 योजनाओं का लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा यह अभियान 12 जनवरी से शुरू किया गया है, जो 31 मार्च 2026 तक चार चरणों में संचालित होगा। स्वामी विवेकानंद जयंती से शुरू हुए इस अभियान के तहत ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, क्लस्टर, विकासखंड और जिला स्तर पर शिविर लगाए जा रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदनों का पंजीयन और निराकरण किया जा रहा है। अभियान के अंतिम चरण में जिला स्तर पर शिविर आयोजित कर शेष आवेदनों का निराकरण किया जाएगा तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा।

पेट्रोल पंपकर्मी को घसीटने वाली कार के आरोपी चालक का पिता गिरफ्तार

चालक डीजल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए वहां से भाग गया

इंदौर। पेट्रोल पंप कर्मचारी की जान लेने वाले आरोपी की पहचान हो गई है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी हीरानगर इलाके का रहने वाला है। कई किलोमीटर के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस टीम उसकी तलाश में हीरानगर तक पहुंची। पुलिस ने आरोपी के पिता को गुरुवार हिरासत में लिया है, जबकि आरोपी कार लेकर फरार है। सांवेर पुलिस के मुताबिक घटना 11 मार्च 2026 की शाम करीब 4 बजे ग्राम कजलाना स्थित शिवलाल पटेल एंड सन्स पेट्रोल पंप, चारपाई ढाबा के पास की है। यहां एक ग्रे रंग की कार का चालक डीजल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए वहां से भाग रहा था। पेट्रोल पंप पर काम करने वाले रोहित (22) पुत्र शंकरलाल परमार निवासी मालीखेड़ी ने कार को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान उसका हाथ कार के कांच में फंस गया। आरोप है कि चालक ने कार तेज गति से आगे बढ़ा दी, जिससे रोहित कुछ दूरी तक कार के साथ घसीटता चला गया। बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है।

आरोपी की पहचान सीसीटीवी से

पुलिस ने कई जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। जांच में सामने आया कि कार एमआर-10 होते हुए हीरानगर की तरफ गई थी। जानकारी निकालने पर कार आर्यन पुत्र पुणेंद्र तंवर निवासी गौरी नगर के नाम पर मिली। बताया गया है कि आरोपी ने कुछ दिन पहले ही कार खरीदी थी। पुलिस के अनुसार आरोपी अपने दोस्तों के साथ निकला था और घटना के बाद फरार हो गया। गुरुवार सुबह उसे मीडिया के माध्यम से पता चला कि पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जिसके बाद वह कार लेकर घर से भाग गया। फिलहाल पुलिस ने उसके पिता को हिरासत में लिया है और आरोपी की तलाश जारी है।

इंदौर। शहर के व्यस्त बंगाली चौराहे के नजदीक आशीष नगर की अपेक्षाकृत शांत सड़क पर गैस की किल्लत का असर दिखाई दे रहा है। गैस एजेंसी के सामने दिनभर लगने वाले जाम से आसपास के रहवासी और वाहन चालक परेशान हैं। सर्विस रोड़ से लगने वाली इस सड़क पर लगातार यातायात बाधित होता है और दिनभर जाम के हालात बनते हैं। गैस सिलेंडर लेने आने वाले लोग सड़क किनारे वाहन खड़े कर देते हैं। रहवासियों के अनुसार सुबह से शाम तक वाहनों की कतार लगी रहती है, जिससे लोगों को आने-जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

फर्जी एफडी से जमानत, तीन पर केस

इंदौर। जिला न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमानत लेने के मामले में तीन लोगों के खिलाफ दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए हैं। आरोप है कि एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में फर्जी एफडी के दस्तावेज प्रस्तुत कर आरोपी को जमानत दिलाई गई थी। एमजी रोड पुलिस के अनुसार जाकिर पिता माजिद हुसैन निवासी सदर बाजार, मोहसिन पिता एजाज निवासी जावरा और शाहनवाज पिता एजाज खान के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया कि जाकिर ने मोहसिन की जमानत के लिए एक लाख रुपये की एफडी का दस्तावेज अदालत में पेश किया था। इसके आधार पर कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी थी। शर्त के अनुसार राशि सात वर्ष तक जमा रहना थी, लेकिन जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद ही एफडी की राशि निकाल ली गई। वकील की आपत्ति के बाद मामले की जांच हुई और अदालत ने मोहसिन की जमानत निरस्त कर दी। पुलिस अब तीनों आरोपियों की तलाश में जुटी है।

ओपीडी के 600 रू लेने की तैयारी पर न विशेषज्ञ डॉक्टर, न सुविधाएं

आयुष्मान योजना के तहत भी 13 मरीज, जिनमें से 7 बच्चे

इंदौर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में न तो अलग ओपीडी ब्लॉक है और कई विभागों में प्रोफेसर के पद भी खाली पड़े हैं। इसके बावजूद प्रबंधन 1 अप्रैल से 600 रु. फीस वाली पेड ओपीडी शुरू करने की तैयारी में है। यह फैसला सवालों के घेरे में है। सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल की स्थिति यह है कि कई विभाग एक या दो डॉक्टरों के भरोसे चल रहे हैं। जबकि, कुछ में तो विभाग अध्यक्ष तक नहीं हैं। हर विभाग में डॉक्टरों के बैठने के लिए सिर्फ दो चैंबर हैं। नियमित ओपीडी व्यवस्था ही पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। अस्पताल की क्षमता 400 बेड की बताई जाती है। लेकिन, 11 मार्च को रिकॉर्ड में केवल 143 मरीज भर्ती मिले। इनमें 43 मरीज आईसीयू में थे और उसी दिन 17 नए मरीज भर्ती हुए। अस्पताल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस संख्या में डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज भी शामिल हैं। उन्हें अलग कर दिया जाए तो वास्तविक भर्ती मरीजों की संख्या इससे भी कम है। आयुष्मान योजना के तहत भी सिर्फ 13 मरीज दर्ज थे, जिनमें से

7 बच्चे पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग में भर्ती थे।

बने नियम लागू नहीं

चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 2018 में सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के संचालन के संशोधित नियम जारी किए थे। इनमें नियमित ओपीडी समय के बाद पेड ओपीडी का प्रावधान रखा गया था। लेकिन इंदौर में यह व्यवस्था करीब 8 साल तक लागू ही नहीं हो सकी। 5 विभाग में प्रोफेसर, दो में असिस्टेंट प्रोफेसर तक नहीं हैं। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और हेड एंड नेक सर्जरी में प्रोफेसर नहीं हैं। कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी में असि. प्रोफेसर नहीं हैं। 11 सर्जिकल विभागों के लिए एनेस्थीसिया में सिर्फ 5 डॉक्टर हैं। अधिकांश विभागों में एक-दो विशेषज्ञों के भरोसे इलाज चल रहा है।

संचालन स्पष्ट नहीं

2018 में बने नियमों के अनुसार पेड ओपीडी से मिलने वाली राशि का 50त्न डॉक्टरों को प्रोत्साहन के रूप में दिया जा सकता है। जबकि, सर्जरी से होने वाले राजस्व का 20त्न हिस्सा भी डॉक्टरों को मिलने की बात कही गई। लेकिन, इस आदेश में यह स्पष्ट नहीं कि ओपीडी किस भवन में चलेगी, पंजीयन प्रक्रिया क्या होगी और अपॉइंटमेंट सिस्टम कैसे लागू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले नियमित ओपीडी और स्टाफ व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है।

सिलेंडर की कालाबाजारी पर सख्ती, जिला प्रशासन ने बनाया कंट्रोल रूम

कंट्रोल रूम पर शिकायत के लिए नंबर और नाम जारी किए गए

इंदौर। एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन सख्ती कर रहा है। जिला प्रशासन ने उपभोक्ताओं की सुविधा और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए कंट्रोल रूम बनाया। अब आम उपभोक्ता गैस सिलेंडर से जुड़ी किसी भी समस्या, शिकायत या सुझाव के लिए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकेंगे। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की सहज उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर यह कंट्रोल रूम बनाया गया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर 0731-2993900 जारी किया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू ने बताया कि इंदौर जिले में गैस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी से बचाने तथा घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री व कालाबाजारी पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है।

कंट्रोल रूम पर तैनात- सहायक आपूर्ति अधिकारी, कल्पना परामानिक (मोबाइल नम्बर-9399142251) कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, सवेसिह गामड़ (8120041922) सहित कम्प्यूटर ऑपरेटर, अंकित नागर (9200249020) रोहित बर्मन (8085799812) महेश जगताप (6260271176) अब्दुल समद (9926062731) उपभोक्ता इन हेल्पलाइन नंबर पर अपनी शिकायत या सुझाव कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 0731-2993900 पर दर्ज करा सकते हैं या फिर कलेक्टोरेट ऑफिस के रूम नंबर 221 में ऑफिस के समय खुद आकर भी जानकारी दे सकते हैं। कंट्रोल रूम प्रभारी और उनकी टीम प्राप्त शिकायतों को दर्ज कर उनके त्वरित निराकरण की कार्रवाई करेगी।

बिना हेलमेट पहने बुलेट की टंकी पर युवती को बैठाया, पुलिस जांच शुरू

इनफ्लुएंसर का वीडियो वायरल, रील के चक्कर में तोड़े नियम

इंदौर। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने की होड़ में कुछ इनफ्लुएंसर अब कानून और सुरक्षा की भी अनदेखी कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया है, जहां सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर 'ओए इंदौरी' का यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए बनाया गया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में इनफ्लुएंसर बिना हेलमेट के बुलेट मोटरसाइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक युवती बाइक की टंकी पर बैठी दिखाई दे रही है। हैरानी की बात यह भी है कि जिस बुलेट से यह स्टंट किया गया, उस पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई दिखाई दे रही है। शहर की

व्यस्त सड़कों पर इस तरह का खतरनाक स्टंट न केवल उनकी अपनी जान को खतरे में डालता है, बल्कि अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर जोखिम पैदा करता है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला पुलिस के संज्ञान में आया। एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि वीडियो सामने आते ही पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। संबंधित व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्रवाई की जा रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने भी स्पष्ट किया है कि कानून तोड़कर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर धमकाकर 40.70 लाख की ठगी, एक पकड़ाया

सीनियर सिटीजन को पुलिस-सीबीआई का डर दिखाकर कारनामा

इंदौर। शहर में फर्जी 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर एक सीनियर सिटीजन से 40 लाख 70 हजार रुपए की ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के फरार आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और ठगी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था।

क्राइम ब्रांच के अनुसार 71 वर्षीय रिटायर्ड इंदौर निवासी फरियादी ने एनसीआरपी पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 3 अक्टूबर 2024 को सुबह करीब 10 बजे उनके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि मुंबई स्थित केनरा बैंक से उनके नाम पर 2 करोड़ 60 लाख रुपये का संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है और मामले में जांच चल रही है।

आरोपियों ने खुद को पुलिस और सीबीआई से जुड़ा बताते हुए कोर्ट के फर्जी आदेश और दस्तावेज भेजकर पीड़ित को डराया। गिरफ्तारी का भय दिखाकर उनसे एफडी तुड़वाकर अलग-अलग किश्तों में कुल 40.70 लाख रुपये ट्रांसफर करवा लिए। शिकायत के बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि इस मामले में पहले सूरत निवासी हिम्मत भाई देवानी और कच्छ निवासी अतुल गिरी गोस्वामी को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब फरार आरोपी पीयूष परमार को भी सूरत से पकड़ लिया गया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी गैंग के लिए बैंक खाते उपलब्ध कराते थे, जिनके जरिए ठगी की रकम ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस ने अब तक इस मामले से जुड़े 23 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है।

सेवाधाम में मौतों पर हाई कोर्ट में रिपोर्ट पेश, चिकित्सा इंतजाम नहीं

इसके कारण बीमार आश्रितों को सही उपचार मिलना मुश्किल

इंदौर। युगपुरुष आश्रम में 10 बच्चों की मौत के बाद उज्जैन के सेवाधाम आश्रम भेजे गए 86 बच्चों में से 17 की मौत के मामले में हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज की थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सेवाधाम आश्रम में 1056 दिव्यांग और परित्यक्त लोग रह रहे हैं, लेकिन वहां तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसे बड़ी कमी माना गया है। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। रिपोर्ट के अनुसार 7 मार्च को एमिकस क्यूरी वरिष्ठ अधिवक्ता अमित एस अग्रवाल और उप महाधिवक्ता सुदीप भार्गव ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आश्रम का निरीक्षण किया, तब कलेक्टर, एसपी भी मौजूद थे।

सामने आई खामियां

आश्रम में 1000 से अधिक दिव्यांग और परित्यक्त लोग रहने के बावजूद इलाज के लिए स्थायी मेडिकल वार्ड या इमरजेंसी सुविधा नहीं है। इतने बड़े आश्रय गृह में नियमित डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ की स्थायी नियुक्ति नहीं है, जिससे बीमार आश्रितों को तुरंत उपचार मिलना मुश्किल होता है। मानसिक रोगियों के उपचार के लिए 23 प्रकार की दवाओं के लिए करीब 7.70 लाख रुपए का प्रस्ताव भेजा गया है, यह अब तक स्वीकृत नहीं। आश्रम के सभी निवासियों के यूडीआईडी, आधार और आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, जिससे कई लोगों को सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा।

रिश्वतखोर प्रबंधक को चार साल की सजा

इंदौर। आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था के प्रबंधक को रिश्वत लेने के मामले में विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) झाबुआ ने चार वर्ष के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सेल्समैन पद पर निलंबन के बाद पुनः सेवा में बहाली के आदेश जारी करने के लिए प्रबंधक द्वारा 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने शिकायत की तस्दीक की,जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद 27 सितंबर 2016 को ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी लवलेश राठौर को 50 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया।

23 कार्यक्रमों में 3700 हेलमेट वितरित

इंदौर। सड़क सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 'हेलमेट पहने-सुरक्षित रहें' अभियान के तहत लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को पलासिया चौराहे पर वृहद हेलमेट जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस उपायुक्त (प्रभारी यातायात) राजेश कुमार त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा अब तक 23 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर 3700 से अधिक हेलमेट जरूरतमंद वाहन चालकों को वितरित किए जा चुके हैं, ताकि लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हादसों से बच सकें। अभियान के दौरान ऐसे दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट प्रदान किए गए जिनके पास वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज मौजूद थे, लेकिन वे हेलमेट नहीं पहन रहे थे। वहीं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के चालान भी किए गए और उन्हें सड़क सुरक्षा का महत्व समझाते हुए हेलमेट पहनने की सलाह दी गई। इस अवसर पर कई जिम्मेदार वाहन चालक स्वेच्छा से हेलमेट पहनकर पहुंचे, जिनकी पुलिस अधिकारियों ने सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित भी किया।

संपादकीय

अब सीईसी के खिलाफ अविश्वास

लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद अब विपक्ष संसद में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसके लिए जरूरी नोटिस पर लोकसभा के 130 तथा राज्यसभा के 63 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। जबकि जरूरत क्रमशः 100 और 50 सांसदों के दस्तखत की ही है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सर्वाधिक उत्साह में तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस हैं, जो वर्तमान सीईसी ज्ञानेश कुमार को पद से हटाना चाहते हैं। उनके साथ इंडिया गठबंधन के घटक दल व आम आदमी पार्टी भी हैं। इस प्रस्ताव को चर्चा के लिए दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। विपक्ष ने सीईसी पर सात गंभीर आरोप लगाए हैं। इनमें पक्षपातपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालने और 'बड़े पैमाने' पर मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करना प्रमुख हैं। तृणमूल कांग्रेस का तो सीधा आरोप है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों का आशय यही है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी पूरी करने की जगह भाजपा के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। जबकि सीईसी का काम निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराना होता है। गौरतलब है कि ज्ञानेश कुमार पहले सीईसी हैं, जिनकी नियुक्ति मोदी सरकार द्वारा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में संविधान संशोधन के बाद हुई है। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की समिति से बाहर करने के लिए था। जबकि वह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही की गई थी। इस संशोधन के बाद देश में संदेश यह गया कि सरकार अपने किसी खास व्यक्ति को इस महत्वपूर्ण पद पर बिठाना चाहती है, जो पूरी तरह से सरकार के हितों के अनुकूल काम करे। सीईसी नियुक्ति के लिए तीन सदस्यीय समिति में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के नाम असहमति जताई थी, इसके बावजूद सरकार ने उन्हें ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तलवारें तभी से खिंची हुई हैं। ज्ञानेश कुमार के अभी तक के आचरण और कार्यशैली से विपक्ष का शक और गहराया है। अविश्वास प्रस्ताव उसी की परिणति है। यहां बड़ा सवाल यह है कि क्या यह प्रस्ताव संसद में पारित हो पाएगा? क्योंकि सीईसी को हटाने की प्रक्रिया भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों को हटाने जितनी ही जटिल है। संविधान के अनुसार उन्हें केवल 'कदाचार' अथवा 'अक्षमता' के आधार पर ही हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत होने के बाद उसे पारित कराने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत चाहिए। इस हिसाब से दोनों सदनों में इस प्रस्ताव के पारित होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि सत्ता पक्ष किसी कीमत पर ऐसा नहीं होने देगा। जहां तक विपक्ष की बात है तो वह स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी बहुत गंभीर नहीं था, और शायद इसमें भी नहीं रहे। इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। राहुल को स्पीकर के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर बोले ही नहीं। उलटे केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को बेनकाब कर दिया। यही नहीं विपक्ष ने स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में मत विभाजन नहीं मांगा और प्रस्ताव ध्वनिमत से खारिज हो गया। ऐसे में प्रश्न यह उठता है कि सीईसी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कवायद भी स्पीकर की तरह महज संदेश देने की है या फिर विपक्ष सचमुच उन्हें हटाने के लिए गंभीर है।

बिहार से नीतीश कुमार की विदाई के मायने

नजरिया

अवधेश कुमार
लेखक दिल्ली निवासी वरिष्ठ पत्रकार हैं।

हमारी राजनीति, मीडिया और बौद्धिक जगत में संदेह का मनोविज्ञान इतना हावी है कि ऐसे किसी कदम को सहज स्वाभाविक स्वीकार नहीं किया जा सकता। विरोधी इसमें षड्यंत्र देख रहे हैं तो इसका उत्तर राजनीति और समाज के चरित्र में है। अपने व्यक्तित्व या अभी तक की घटनाओं के संदर्भ में देखते हैं तो यही निष्कर्ष आएगा। चूंकि भारतीय राजनीति में इस तरह के उदाहरण नहीं है, इसलिए यह असामान्य घटना लगती है। लगभग दो दशक प्रदेश का प्रत्यक्ष नेतृत्व करने के बाद इस निर्णय को सहज स्वीकार करना आसान नहीं होता। उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक वर्ग में भावनात्मक उबाल भी है। कुछ समय बाद धीरे-धीरे यह समाप्त हो जाएगा। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में इतना पाखंड है कि कल तक जो लोग नीतीश कुमार को मानसिक रूप से असंतुलित होने की बात कर वीडियो वायरल करा रहे थे, बयान दे रहे थे वे भी इसमें भाजपा का षड्यंत्र देख रहे हैं।

नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाना ऐसी घटना है जिस पर लंबे समय तक चर्चा होगी। राजनीति के छात्र भविष्य में इस पर शोध भी करेंगे ।

भारतीय राजनीति में लंबे समय तक सत्ता शीर्ष पर बने रहने के बाद जब भी कोई स्वयं निवृत होने का फैसला करेगा या नहीं करेगा तब - तब इसे उदाहरण के रूप में पेश किया जाएगा। हमारी राजनीति, मीडिया और बौद्धिक जगत में संदेह का मनोविज्ञान इतना हावी है कि ऐसे किसी कदम को सहज स्वाभाविक स्वीकार नहीं किया जा सकता। विरोधी इसमें षड्यंत्र देख रहे हैं तो इसका उत्तर राजनीति और समाज के चरित्र में है। अपने व्यक्तित्व या अभी तक की घटनाओं के संदर्भ में देखते हैं तो यही निष्कर्ष आएगा। चूंकि भारतीय राजनीति में इस तरह के उदाहरण नहीं है, इसलिए यह असामान्य घटना लगती है। लगभग दो दशक प्रदेश का प्रत्यक्ष नेतृत्व करने के बाद इस निर्णय को सहज स्वीकार करना आसान नहीं होता। उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के एक वर्ग में भावनात्मक उबाल भी है। कुछ समय बाद धीरे-धीरे यह समाप्त हो जाएगा। राजनीति और सार्वजनिक जीवन में इतना पाखंड है कि कल तक जो लोग नीतीश कुमार को मानसिक रूप से असंतुलित होने की बात कर वीडियो वायरल करा रहे थे, बयान दे रहे थे वे भी इसमें भाजपा का षड्यंत्र देख रहे हैं। याद करिए जब एक मुस्लिम लड़की को नियुक्ति पत्र सौंपते समय उन्होंने अभिभावकीय भाव में हिजाब पड़कर यह कहते हुए कि क्या लगाई हो हटाओ खींचने की कोशिश की तो कितना बड़ा मुद्दा बनाया गया? वे भी नीतीश के नाम पर छाती पीट रहे। क्या हम राजनीति में ऐसी ही प्रवृत्ति चाहते हैं जहां कोई कभी अपने तरीके से सत्ता शीर्ष से निवृत होने का कदम उठाये ही नहीं? या उन्हें इसके लिए सम्मानपूर्वक तैयार करने की कोशिश नहीं हो? आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो इसे सकारात्मक दृष्टि से देखिए।

ऐसी घटना के पीछे निश्चित रूप से कुछ कारण और बड़े प्रयास भी होंगे। अंततः परिणति ही मुख्य अर्थ रखती है। यह कहना कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनना चाहती थी इसलिए उन्हें हटा दिया गया नीतीश कुमार के व्यक्तित्व को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी टिप्पणी करने वाले नीतीश कुमार को दुर्बल या खोखला व्यक्तित्व साबित कर रहे हैं। भाजपा नेतृत्व में अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा हो सकती है किंतु इसके लिए नीतीश को जबरन हटाकर गठबंधन में विपरीत संकेत देंगे यह मानने का कोई कारण नहीं है। लोकसभा में भाजपा को बहुमत नहीं होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार जदयू और तेलुगू देशम की बदौलत चल रही है।भाजपा नेतृत्व क्या किसी नेता, उनके सहयोगियों या पार्टी से दुर्व्यवहार करने का जोखिम उठायेगी? आम दुष्प्रचार के विपरीत भाजपा अपने गठबंधन के साथियों को सम्मान देती है। महाराष्ट्र में भाजपा ने शिवसेना उद्धव ठाकरे को नहीं छोड़ा बल्कि उन्होंने भाजपा को छोड़ा। नीतीश कुमार को कभी भाजपा ने नहीं छोड़ा उन्होंने ही पाला बदल किया लेकिन जब वापस आए तो सरकार चलाने एवं निर्णय लेने की पूरी स्वतंत्रता रही। 2020 में भाजपा को जद यू से ज्यादा सीटें थीं फिर भी मुख्यमंत्री उन्हें ही बनाया। नीतीश पर दबाव डालकर ऐसा कराया जा सकता है यह उनके चरित्र के साथ मेल नहीं खाता। नीतीश कुमार ने जब चाहा भाजपा को छोड़ा और फिर अपनी इच्छा से राजद छोड़ भाजपा के साथ आये। तो फिर?

उन्होंने एक्स पर लिखा है कि संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूँ। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूँ। कहां जा रहा है कि कारण कुछ और है, यह स्क्रिप्ट औरों ने लिखकर उनकी विदाई का झूठा आधार प्रस्तुत किया है। ऐसा क्या कारण हो सकता है जिसके लिए नीतीश को झूठ बोलना पड़े? प्रत्यक्ष कोई कारण नजर नहीं आता। क्या यह संभव है कि भाजपा नीतीश को दबाव में लाकर मुख्यमंत्री पद से हटने के लिए मजबूर करे और वे इसे सहन कर जाएं? किसी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की इच्छा हो और उसे जबरन हटाने की कोशिश होगी तो वह सरकार गिरा देगा। जिस सरकार का मुखिया नहीं हो उसे बनाए रखने में क्या रुचि हो सकती है। तो यह तर्क गले नहीं उतरता। मान लीजिए उन्होंने राज्यसभा को विदाई का बहाना बनाया तो इससे साबित नहीं होता कि किसी दबाव में थे। पिछली बार जब वह राजद के साथ गए थे तो तेजस्वी यादव के सामने घोषणा किया था कि अब अब हम आगे बहुत दिन नहीं रहेंगे और यही लोग आगे बढ़ाएंगे। अपने साथियों से बोलते थे कि अब हम मुख्यमंत्री पद से अलग होना चाहते हैं।

यह बात सही है कि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार के व्यवहार, वचन और भाव में अस्वाभाविकता, असहजता और असंतुलन प्रदर्शित होता था। इन कारणों सेसमस्याएं आतीं थीं और दोनों पार्टी के नेताओं को हैंडल करना पड़ता था। इसलिए संभव है उन्हें मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश हुई होगी। मुख्य बात निर्णय और उसके समय का है

सही समय पर लिए गए या कराए गए निर्णय का भी महत्व होता है और यह कई बार इतिहास के लिए उदाहरण भी बन जाता है। नीतीश कुमार के लिए इससे उपयुक्त अवसर सत्ता शीर्ष से अलग होकर तत्काल सक्रिय रहने का क्या हो सकता है? उनके नेतृत्व में गठबंधन भारी बहुमत के साथ सत्ता मे है, राजनीतिक स्थिरता है, उनके विरुद्ध असंतोष का भाव नहीं है, विकास की गाड़ी पटरी पर है और सक्रिय रहने के लिए राज्यसभाकी सदस्यता है। शायद वे सीधे निवृत्ति की घोषणा करते तो विरोध ज्यादा उग्र और हिंसक हो सकता था। तो समर्थकों को समझाने के लिए उनके पास राज्यसभा में जाने की इच्छा का एक आधार है।

सच कह तो यह अवसर नीतीश कुमार के संपूर्ण राजनीतिक जीवन, उनके योगदान आदि का निष्पक्ष मूल्यांकन का है। बिहार का नेतृत्व भाजपा के समर्थन से उन्होंने तब संभाल जब प्रदेश गहरे निराशा, हताशा और अवसाद से ग्रस्त था। बिहार में कुछ हो सकता है इसकी कल्पना ही नहीं थी। भारत और उसके बाहर बिहार कुशासन, अविकास, सामाजिक जातीय तनाव, नेताओं के भ्रष्टाचार का शर्मनाक उदाहरण बन गया था। बिहार शब्द गाली हो गई थी और स्वयं को बिहारी कहने में लोग शर्म महसूस करते थे। नीतीश के नेतृत्व में जनता दल यू और भाजपा ने बिहार में न केवल आशा, उम्मीद और उत्साह पैदा किया बल्कि कानून और व्यवस्था पुर्नस्थापित कर प्रदेश को विकास के रास्ते सरपट दौड़ा दिया। पिछले लंबे समय से इसका विकास दर शीर्ष राज्यों के समान या कई बार आगे रहा है। लेकिन ध्वस्त हो चुके प्रदेश को वहां तक ले जाना आसान नहीं है। हालांकि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के सामाजिक न्याय के नाम पर जातीय विभाजन और टकराव बनाए रखना एवं सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम परस्त नीति की काट के लिए पिछड़ों में अति पिछड़े, दलित में महा दलित, मुसलमान में पसमांदा आदि समूह खड़े किए और इससे जातिवाद दूसरे रूप में मजबूत हुआ। किंतु उनके कल में किसी तरह का जाति संघर्ष नहीं होना भी सच्चाई है। दूसरे, लड़कियों और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के कदम उनके दूरदर्शी विजन और लैंगिक समानता के प्रति सच्ची प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं। जहां लड़कियां डर से स्कूल कॉलेज जाने से बचती थी वहां सीमित संसाधनों में उनके लिए साइकिल, वस्त्र, पुस्तकों और प्रोत्साहित करने के लिए वजीफे आदि की व्यवस्था ने चमत्कार कर दिया। हालांकि इन सबके पीछे भाजपा की भी भूमिका थी किंतु आज जब हम उनका मूल्यांकन करते हैं तो ये सब उनके योगदान में जुड़ेंगे। महिलाओं को स्थानीय निकाय में 33 प्रतिशत आरक्षण की सामाजिक वर्णक्रम बदलने में ऐतिहासिक भूमिका थी। अगर कुछ निहित स्वार्थी बुद्धिजीवियोंऔर समर्थकों के प्रभाव में आकर सेकुलरिज्म के नाम पर उन्होंने 2013 में तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध अतिवादी रवैया अपनाते हुए गठबंधन नहीं तोड़ा होता, राजद के साथ नहीं गए होते तो उनके ऐतिहासिक योगदान निर्दोष होते। 2010 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव का संपूर्ण परिवार पराजित हो गया था, पार्टी न्यूनतम वोट और सीटों पर आ गई थी। इसके अंत के साथ बिहार में विपक्ष की नई राजनीति के उभरने की संभावना थी। उन्होंने 2015 में साथ चुनाव लड़कर राजद को जीवन दान दिया। इस भूल के लिए उन्हें पश्चाताप होगा। पर उन पर किसी तरह के वित्तीय भ्रष्टाचार, परिवारवाद आदि का आरोप नहीं लगा और यही सच्चाई है। उनके पुत्र इतने समय बाद राजनीति में आ रहे हैं तो इसे परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं कह सकते। सत्ता शीर्ष से स्वयं को अलग करने के कदम पर ऐसे व्यक्ति का अभिनंदन होना चाहिए, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। भाजपा नेतृत्व एवं जदयू के वरिष्ठ नेताओं की भी सराहना होनी चाहिए कि उन्हें इसके लिए उचित व सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराया। इसे राजनीति में एक प्रवृत्ति स्थापना मान लें तो लोकतंत्र की दृष्टि से इसका संदेश मंगलकारी होगा।

ईरान-अमेरिका युद्ध परिणाम और भारत का पक्ष

सामयिक

डॉ. अंशुल उपाध्याय
फॉर्मर यूजीसी सीनियर फैलो (रक्षा एवं स्ट्रेटजिक अध्ययन विभाग)

अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर बड़े हमले किए गए। जिनका मुख्य कारण ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना, उसके बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को नष्ट करना और क्षेत्र में ईरानी शासन के खतरों को समाप्त करना बतलाया गया है। अमेरिका ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कार्प्स (आईआरजीसी) के खतरों को खत्म करने और मध्य पूर्व में ईरानी प्रभाव को कम करने के लिए ये सैन्य कार्रवाई की। इस कार्यवाही में (अयातुल्ला अली खामेनेई) जो कि ईरान के सरगना थे मारे गए। फिर भी अमेरिका ने इस्फ़हान, कराज, करमानशाह, क़ुम और तब्रीज़ में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर अतिरिक्त हमले किए। जिसके बाद ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात सहित पूरे मध्य पूर्व में इज़राइल और अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं।

ईरान कम से कम 1957 से परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, जिसमें उसे अलग-अलग स्तर की सफलता मिली है। ने 1990 के दशक में इस कार्यक्रम के अनुसंधान में सहयोग के लिए चीन और रूस के साथ कई समझौते किए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए अन्य देशों के द्वारा भी गहन प्रयास किए गए। जिसके लिए ईरान सहमत तो हो गया, लेकिन उसने केवल परमाणु ऊर्जा के लिए अपने सेंट्रीफ्यूज रखने पर जोर दिया। हालांकि, उसने आईएईए को पारदर्शी रिपोर्टिंग करने की अपनी प्रतिबद्धता का पालन नहीं किया और गुप्त गतिविधियां जारी रखीं परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में मामला भेज दिया गया। जिसके बाद ईरान पर कई प्रतिबंध लगाए गए 2011 और 2015 के बीच, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के बढ़ते प्रभावों के कारण ईरान की स्थिति बिगड़ गई। और वहां की अर्थव्यवस्था गिर गई साथ ही बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई।

इसके बाद ईरान में हसन रूहानी सरकार के सत्ता में आ जाने के बाद 2015 में जेसीपीओ पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रमुख पक्षों द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसे मंजूरी दे दी।संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव 2231, प्रतिबंधों में राहत का मार्ग प्रशस्त करता है।हालांकि जेसीपीओ ने ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर दिया, लेकिन उसकी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं बढ़ती रहीं। ईरान ने अपनी इन महत्वाकांक्षाओं को जारी रखा।इसके माध्यम से शिया उग्रवादियों को हथियारबंद करना और प्रशिक्षण देना आदि सम्मिलित था।ईरान ने फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास को वर्षों तक सैन्य सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया था, जिसके चलते 7 अक्टूबर, 2023 को हमास ने इज़राइल पर हमला किया था।

ट्रम्प प्रशासन ने ईरान को दबाव में लाने के लिए अधिकतम दबाव की रणनीति अपनाई। बातचीत की मेज पर, ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर जेसीपीओ के प्रतिबंधों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। अप्रैल 2019 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने आईआरजीसी को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। 2024 में हुए ईरान इजराइल युद्ध के बाद अमेरिका ने इजराइल का सहयोग करते हुए ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। ईरान के तेल के ठिकानों, रक्षा उपकरणों के उत्पादन केंद्र को भी निशाना बनाने की बात ट्रंप प्रशासन द्वारा की गई है।

भारत का पक्ष

एक और जब भारत एशिया की उभरती हुई महाशक्ति बनने जा रहा है ऐसे में अमेरिका और ईरान के मध्य ये जंग सम्पूर्ण विश्व को ऊर्जा संकट में डालने के लिए काफ़ी हैं। एक ओर जहां भारत और इजराइल संबंधो की घनिष्ठता है दूसरी और अमेरिका के साथ भी हमारे संबंध पहले से बेहतर होते जा रहे हैं अब ईरान के साथ भी भारत के व्यापारिक संबंध है। इन हालातों में भारत को शांति का ही पक्षधर बनना उचित होगा। विवाद के समाधान के लिए दोनों पक्षों को आपस मे बैठकर मुद्दे सुलझाने होंगे। क्योंकि अगर अमेरिका नहीं रुका तो ईरान को सहयोग देने वाले राष्ट्र भी ईरान के कंधे में बंदूक रखकर चलाएंगे और संपूर्ण एशिया में भयंकर तबाही होगी आने वाले कई सालों का ईंधन चंद दिनों में धू धू कर के जल जाएगा। जिन ऊर्जा संसाधनों के लिए युद्ध हो रहे हैं यदि उनके श्रोत ही नष्ट कर दिये गए तो फिर हमारे हाथ में राख के ढेर के सिवा आखिर क्या बचेगा।

भारतीय सभ्यता में 'इच्छामृत्यु' सदैव अस्वीकार?

फैसला

डॉ. रमेश ठाकुर
सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान भारत सरकार

इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पहली समहति देकर जनमानस में नई किस्म की बहस को जन्म दे दिया है। बहस ऐसी है जिसमें सिर्फ भावनाओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। गाजियाबाद निवासी 32 वर्षीय हरीश राणा की इच्छामृत्यु पर दिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक ऐसा भावनात्मक फैसला है जो भारतीय न्याय व्यवस्था के इतिहास में पहली मर्तबा लिया गया। कोर्ट के आदेशानुसार इच्छा मृत्यु पर सभी प्रक्रियाएं बेशक मानवीय ढंग से और चिकित्सीय निगरान में होंगी, लेकिन फैसला देने वाली पीठ के जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन खुद भी भावुक हो गए। उन्होंने स्वीकारा कि ये निर्णय देना उनके लिए बहुत कठिन था। पर, उन्हें अपने फैसले के जरिए एक व्यक्ति को उनके निष्क्रिय शरीर से होती अंतन पीड़ा से मुक्ति भी दिलवाना था जिसका उन्होंने कानूनी मर्यादयों में रहकर अपना फर्ज निभाया।

ये मामला अगस्त 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट से खारिज होकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। लेकिन यहां भी जजों की एकमत राय नहीं थी। काफी विमर्श के बाद शीर्ष कोर्ट ने 'मेडिकल बोर्ड' को गठित' करने का आदेश दिया। बोर्ड की जब रिपोर्ट पहुंची, जिसमें चिकित्सकों ने बताया कि हरीश का शरीर शत-प्रतिशत निष्क्रिय हो चुका है इसलिए वह इच्छामृत्यु का हकदार है। फिलहाल, इच्छामृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय ने जीवन के असमय अंत की चाहत पर समकालीन स्वास्थ्य देखभाल में ऐसी प्रथाओं की भूमिका पर अनोखी बहस को छेड़ा है जिसकी चर्चा लंबे समय तक होगी। यह बहस सभ्य समाज के कानूनी, नैतिक, मानवाधिकार, स्वास्थ्य, धार्मिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जटिलताओं और गतिशील पहलुओं को भी सोचने पर विवश करेगी।

गौरतलब है, इच्छामृत्यु शब्द की उत्पत्ति भारत में नहीं, ग्रीस में हुई थी, जिसका अर्थ होता है एक सुखद मृत्यु कानून में जीवन का अधिकार' अनुच्छेद 21 में निहित है जो एक प्राकृतिक अधिकार भी। लेकिन आत्महत्या जीवन का अप्राकृतिक अंत है और इसलिए 'जीवन के अधिकार' की अवधारणा के साथ असंगत और विरोधाभासी भी है। भारत में आत्महत्या गैरकानूनी होने के बावजूद भी नहीं रूकती। लेकिन इच्छामृत्यु का नाम सुनकर न सिर्फ रोंगटे खड़े होते हैं, बल्कि भावनाओं का समुद्र हिचकौले मारने लगता है। समूचे विश्व में भारतीय सभ्यता सदैव से उदारवादी मानी गई है। इस लिहाज से कोई भी व्यक्ति किसी को मरने के लिए नहीं बोल सकता? लेकिन हरीश राणा का मामला सबसे इतर है। बीते 13 वर्षो से उनके दर्द भरे जीवन को और लंबा नहीं खींचा जा रहा है। हरीश को विरह भरे जीवन से मुक्ति दिलवाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं? शीर्ष अदालत ने हरीश के शरीर से जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति दे दी है जिसे चिकित्सकीय निगरानी में उनकी अंतिम सांसों को प्राकृतिक बनाया जाएगा।

बेशक ये निर्णय पहला है, पर आखिरी हो? आखिरी इसलिए, अगर इच्छा मृत्यु पर निर्णय देने का सिलसिला आगे भी चला तो इसके दुरुपयोग होने लगेंगे। क्योंकि समाज में नैतिकता और न्याय का पतन तेजी से जारी है। भारत के कोने-कोने में ऐसे असंख्य मामले भरे हैं जहां बीमार बुजुर्गों के परिजन उनकी धन-दौलत, संपत्तियों पर कब्ज़ा करने के लिए उनके मरने का इंतजार में हैं। ऐसे में वो भी उनकी इच्छामृत्यु की चाह लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने लगेंगे। इस मसले पर केंद्र सरकार कोई समग्र कानून या कोई व्यापक व्यवस्था बनाना होगा। हालांकि, इस फैसले को शीर्ष कोर्ट ने 2018 के कॉमन कॉज को कानूनी रूप से पैसिव यूथेनेशिया के तहत दिया है जिसे बार-बार नहीं दोहराया जा सकता। हरीश का ये केस रियर और दुर्लभ श्रेणी का है। फैसले के बाद पूरा हिंदुस्तान हरीश राणा के माता-पिता के जिगरे को भी सलाम कर रहा है।

हरीश के साथ ये दुखद घटना अगस्त-2013 में रक्षाबंधन पर्व के दिन घटी थी। तब, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वह सिविल इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र था। अचानक हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर पड़ा। गिरने के बाद उसके ब्रेन में गहरी इंजरी हुई। तब से लेकर आज तक तमाम चिकित्सीय सुविधाएं दी गई, लेकिन सभी बेबसर साबित हुई। पिछले साढ़े 13 सालों से वह अचैत अवस्था में बिस्तर पर है। सारे डॉक्टर हार गए, कोई दवा काम नहीं आई। हार कर माता-पिता घर उसे ले आए और लाइफ सपोर्ट सिस्टम के सहारे कर दिया। इस दरम्यान माता-पिता की समूची जिंदगी आर्थिक और मानसिक रूप से बेटे के स्वस्थ होने की चाह में तबाह हो गई। झूठी आस में बेटे की सेवा करते रहे। लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। आखिर कब तक वह बेटे को जिंदा रखते। माता-पिता शारीरिक रूप से भी जब कमजोर होने लगे तो उन्होंने हाईकोर्ट में इच्छामृत्यु की गुहार लगाई, जो अब कहीं जाकर मंजूर हुई है।

अदालत में लंबी जिरह हुई, कोर्ट द्वारा मंगाई गई 'एम्स अस्पताल' की रिपोर्ट जिससे साफ हुआ कि हरीश के ठीक करने की कोई उम्मीद नहीं? तब, कोर्ट की पीठ ने भावुक होकर इच्छा मृत्यु पर कठोर निर्णय दिया। दरअसल, ऐसा पड़ाव आ चुका था जिसे और लंबा नहीं खींचा जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे सम्मानपूर्वक हरीश राणा को इच्छामृत्यु की इजाजत देकर पूर्णकार्य किया है। कोर्ट ने कहा है कि हरीश को अपार दुख में अब और नहीं रखा जा सकता। मुश्किल फैसला है लेकिन करना पड़ेगा। चिंता और चिता में बिंदी का फर्क है। चिता मृत शरीर को जलाती है पर चिंता जिंदगी को जलाती रहती है। फिलहाल, एकाध दिनों में कोर्ट के आदेशानुसार हरीश के शरीर से जीवन रक्षक प्रणाली को हटाया जाएगा और पूरी मानवीय प्रक्रिया निभाकर उनके नश्वर शरीर को मुक्ति दिलाई जाएगी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए उमेश त्रिवेदी द्वारा पंकज प्रिंटर्स एंड पैकेजिंग, 16, अल्फा इंडस्ट्रीयल पार्क, जाखिया, इंदौर, म.प्र.- 453555 से मुद्रित एवं 662, साई कृपा कॉलोनी, बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने, इंदौर से प्रकाशित।
प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
स्थानीय संपादक
हेमंत पाल
प्रबंध संपादक
रमेश रंजन त्रिपाठी
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2015/ 66040,
Mobile No.: 09893032101
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

ऊपर तक जाने वाली सेवा...

व्यंग्य

भूपेन्द्र भारतीय
लेखक व्यंग्यकार हैं।

उनका कहना है कि भिया हम क्या करें, नीचे से लिया गया माल ऊपर तक जाता है। यह सिर्फ हमारे पास ही नहीं रहता है। हम तो सिर्फ बीच वाले हैं। हम तो जनता व लोकतंत्र की सेवा कर रहे हैं। यह सब सेवा के नाम पर हो रहा है और सेवा करना क्या गलत है? आपको इससे दिक्कत है तो ऊपर वालों से बात करो। मुझे समझ नहीं आया कि यह ऊपर वाला कौन है ? क्या यह ऊपर वाला वहीं है जिसके नाम से कथावाचक पंडालों में बैठी भोली जनता को डराते है या फिर यह ऊपर वाला वहीं है जिसे किसी ने आजतक नहीं देखा। लेकिन मैंने तो इतना ही सुना था कि असली ऊपर वाला तो सिर्फ देता ही आया है, उसने अब तक कुछ किसी से लिया ही नहीं। किसी की सेवा नहीं लेता।सबको सहयोग ही करता आया है। फिर मैंने ऊपर वाले के नाम से लेने वाले से पूछा कि यह ऊपर वाला कौन है ? तो टेबल के नीचे से लेने वाला हँसने लगा। कहने लगा, 'भिया आप भी मजाक अच्छा करते हो, आप तो हमसे लाख गुना अच्छे से ऊपर वाले को जानते हो। आपने तो ऊपर वाले को ऊपर तक पहुंचाने में चुनाव के समय दिन-रात एक की थी और अब आप उन्हें ही भूल गए! आपको भी उनकी सेवा करना चाहिए!' मैं उसके इस प्रश्न का जवाब कैसे देता। जब ऊपर वाले मुझे ही भूल गया हो, मेरी सेवा ही भूल गए। तो अब उसे यह कैसे बताऊँ! अपना दुखड़ा कह देता तो जो थोड़ा बहुत रुतबा बचा था वह भी चला जाता। खैर आजकल नीचे वाले को देने के मामले में नियम व शिष्टाचार हो गया है कि ऊपर वाले के नाम पर अक्सर कुछ न कुछ सेवा शुल्क देना ही पड़ता है। आजकल सभी ऊपर वाले के नाम से लेते तो हैं, लेकिन ऊपर वाला है कि किसी के हाथ तक नहीं आता! ऊपर वाले के पास सब अपनी अपनी प्रार्थनाएं व मांग सूची पहुंचाना चाहते हैं लेकिन सरकारी कार्यालयों में से ऊपर वाले के पास फाईलें जाती हैं ? और जब तक फाईलों में सेवा वजन नहीं होता, फाईलें ऊपर तक नहीं उड़ सकती हैं। लोकतंत्र के मंदिरों में बैठे ऊपर वाले अलग हिसाब किताब से अपनी दुकानें चलाते हैं। उन्हें नीचे वालों के कर्म से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है उन्हें कागजों के साथ जमा माल से लेना देना होता है। इधर के ऊपर वाले इस हिसाब से ही कर्मो का निर्धारण करते हैं। क्योंकि उन्हें भी अपने से ऊपर वालों को कुछ देना होता है। नहीं तो उनसे ऊपर वाले उन्हें नीचे खिसका सकते हैं। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। कब नीचे वाले पर चल जाए कोई भरोसा नहीं। 'लोकतंत्र की सुंदरता यही है कि इसमें एक से बढ़कर एक ऊपर वाले हैं और हर एक ऊपर वाले से बड़ा एक ओर ऊपर वाले का संवैधानिक प्रावधानों के तहत समय समय पर निर्माण व गठन होता रहता है। ताकि ऊपर वाले ऊपर रहे और नीचे वाले नीचे से सेवा उन्हें देते रहें। और वही नीचे वाले नीचे ही लोकतंत्र की सेवा करते रहें। इसे नीचे रेंगते रहना भी कह सकते हैं।'

हमारे बढ़े बुजुर्ग कह गए हैं कि ऊपर वाला सब देखता है, लेकिन वर्तमान समय में ऊपर वाले माल लेते हैं तब कहीं कृपा होती है। तब कहीं नीचे वालों की ओर देखते हैं। कुछ दया करते हैं। अक्सर कहा जाता है कि ऊपर की कमाई को पाप माना जाता है लेकिन यह पाप आजकल पाप पुण्य का हिसाब करने वाले ही ज्यादा करते है। वो बात अलग है कि वे लोग यह पाप स्वयं नहीं करते है, उसके लिए उन्होंने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाकर रखी है जिसमें सबका काम व दाम बराबर बांटकर रखा है। बड़ी अच्छी उचित मूल्य की सेवा दुकानें खोलकर रखी हैं। जिसमें सब ईमानदारी से ऊपर तक उचित सेवा का मूल्य पहुंचाते हैं। अब ऊपर तक जाने के लिए भी ऊपर वाले को पहले कुछ देना होता है तब कहीं नीचे वाले ऊपर पहुंचाते हैं। इसके लिए बकायदा कंपनियां खुल गई है। हो सकता है ऊपर की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए ऊपर वाली नामक बैंकें भी जल्द ही खुल जाए। वैसे विदेश में तो ऊपर की कमाई रखने के लिए बैंक है भी! ऊपर तक जाने वाली इस सेवा का बकायदा विकेन्द्रीकरण होता जा रहा है। गांवों से लेकर शहरों तक यह ऊपर जाने वाली सेवा दिनोंदिन फल-फूल रही है।

जिम्मेदार नागरिक बनने का वक्त

संकट

प्रो. मनोज कुमार

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

सरकार तो अपने स्तर पर संकट से निपटने के लिए तैयारी कर रही है और उसकी कोशिश होगी कि ईंधन की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहे. यह संकट इस बात की आपकी परीक्षा ले रहा है और शायद आगे इम्तहान का दौर जारी रह सकता है और इस स्थिति में आपकी असल परीक्षा होगी कि आप वास्तविक में कितने देशभक्त हैं और ऐसे विकट समय में राष्ट्र का साथ कैसे देते हैं. इस परीक्षा में खरे उतरते हैं, तब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं. यह समय नीति-नियमों और सरकार के व्यवहार की समीक्षा का नहीं है बल्कि हम सब के एक हो जाने का है.

किसी भी किस्म का संकट हमेशा समाधान की ओर लेकर जाता है. और कोई भी संकट स्थायी नहीं होता है. हमारी पीढ़ी ने कोविड महामारी को झेला और अब अमेरिका-इजराइल और इराक के मध्य युद्ध से उपजे हालात से वैश्विक संकट से दो-चार हो रहा है. यह संकट भी स्थायी नहीं हैं लेकिन हालांकि हालात जो हैं, वह इस बात की गवाही नहीं देते कि समस्या का अंत तुरंत होगा और इसके चलते अनेक किस्म के संकट से भारत समेत दुनिया के अनन्य देश जूझ रहे हैं. भारत के समक्ष इस समय सर्वाधिक संकट ईंधन का है. इसके चलते गैस और पेट्रोल की सप्लाई पर असर साफ दिख रहा है. भले ही अभी हाहाकार ना मचा हो लेकिन जिस तरह से लोग पैनिक हो रहे हैं, हालात वैसा ही बन रहा है. इस युद्ध से जो परिस्थिति निर्मित हो रही है, वह किसी सरकार, राजनीतिक दल का नहीं अपितु राष्ट्र के संकट के रूप में देखा जाना चाहिए. सरकार तो अपने स्तर पर संकट से निपटने के लिए तैयारी कर रही है और उसकी कोशिश होगी कि ईंधन की आपूर्ति की निरंतरता बनी रहे. यह संकट इस बात की आपकी परीक्षा ले रहा है और शायद आगे इम्तहान का दौर जारी रह सकता है और इस स्थिति में आपकी असल परीक्षा होगी कि आप वास्तविक में कितने देशभक्त हैं और ऐसे विकट समय में राष्ट्र का साथ कैसे देते हैं. इस परीक्षा में खरे उतरते हैं, तब आप गर्व से कह सकते हैं कि हम सब भारतीय हैं. यह समय नीति-नियमों और सरकार के व्यवहार की समीक्षा का नहीं है बल्कि हम सब के एक हो जाने का है.

इस संदर्भ में मुझे अपने एक वरिष्ठ का कथन याद आता है जिसमें वे कहते हैं-सब सुविधा हो और आप कार्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, यह बड़ी बात नहीं है बल्कि असुविधा में बेहतर कार्य का प्रदर्शन करना आपके कौशल को दिखाता है. लगभग यही स्थिति हम सबके समक्ष है. जब तक ईंधन की आपूर्ति सामान्य थी और युद्ध जैसी कोई स्थिति निर्मित नहीं थी, तब हम राष्ट्रभक्त थे लेकिन अब जब संकट व्यक्ति नहीं, समूचे समाज पर है तो अब हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ना केवल खुद आना ही नहीं होगा बल्कि अन्य को प्रेरित भी करना होगा ताकि जल्द ही स्थिति सामान्य हो सके. युद्ध के पहले भी हम कोविड के संकट से जूझ चुके हैं और इस बड़े संकट महामारी से खुद को निकाल पाने में कामयाब रहे. कोविड हो या युद्ध, यह संकटकालीन स्थितियां हमें राष्ट्र के प्रति निहित जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए प्रेरित करती हैं. हमारी एक बड़ी कमजोरी यह है कि हम जल्दी से ना केवल पैनिक हो जाते हैं बल्कि स्टोर करने की मानसिकता के दास बन जाते हैं. कोविड के समय भी हमने ऐसा ही किया था और

अनेक जरूरतमंदों को हमारी इस मानसिकता से नुकसान भी हुआ था. वर्तमान में भी यही देखने को आ रहा है लोग गैस टंकी स्टोर करने में तुल गए हैं. किसी उपभोक्ता के घर में चार और पाँच गैस सिलेंडर है तो वह सबको भरकर रख लेना चाहता है जबकि जिनके घरों में जरूरत के लायक एक सिलेंडर है, उसे पहले मिलना चाहिए. जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की बात करते हैं तो इस पर अमल करने का वक्त आता है तो हम क्यों नहीं करते हैं? यह यक्ष प्रश्न ऐसे संकटकालीन स्थिति में हमारे समक्ष खड़ा होता है.

इस तात्कालिक संकट में एकजुटता की जरूरत है और इसे हम स्थानीय स्तर पर ही सुलझा सकते हैं. मोहल्ले और चौपालों में आपसी समझदारी से बैठकी कर यह जान लें कि अपने मोहल्ले में कितने घर हैं और प्रत्येक घर को कितनी ईंधन की जरूरत है? फिर आपस में सुविधानुसार एक-दूसरे की सहायता करें. इससे समाज के पैनिक होने से बचा जा सकेगा और सरकार को व्यवस्था करने में सहायता मिलेगी. इसी तरह आवश्यक होने पर ही वाहनों का उपयोग करें और कोशिश करें कि पेट्रोल का खर्च कम से कम हो. कुछ लोग मानकर कर चल रहे हैं कि हमारे पास ईवी है तो हम चिंता क्यों करें? तो वे लोग जान लें कि ईवी के लिए आपको इलेक्ट्रीसिटी की जरूरत होती है और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए भी अपरोक्ष रूप से ईंधन की जरूरत होती है. बेहतर होगा कि ईवी को भी सुरक्षित रखें और आपातकाल में जरूरतमंदों की मदद में उपयोग लाएं. इस तरह छोटे-छोटे उपाय से समाज में पैनिक नहीं फैलेगा बल्कि स्वास्थ्य और पर्यावरण को बेहतर करने की दिशा में मदद मिलेगी. ऐसा हमने कोविड के दरम्यान देखा है.

सरकारों को चाहिए कि वे आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर वर्कफ्रॉम होम की पॉलिसी लागू कर दे जिससे ईंधन की बड़ी मात्रा में बचत होगी. पर्यावरण को इसका लाभ मिलेगा ही और जीवन सहज हो जाएगा. वर्कफ्रॉम होम की पॉलिसी से लाभ यह होता है कि अनेक अकारण स्थापना खर्च में भी कटौती होती है. साथ ही जरूरत पडने पर व्यक्ति हर समय उपलब्ध होता है. कार्यालयीन समय का बंधन नहीं होता है, इसमें वह भी नहीं है. सरकार अपने स्तर पर व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में काम कर रही है और यह संकट स्थायी नहीं है. समाज और सरकार साथ मिलकर चलेंगे तो स्थिति से निपटने में आसानी होगी. फिलवक्त संकट बहुत भयावह नहीं है लेकिन हमारा डर उसे भयावह बना रहा है. बहुत जल्द ही हम तनाव मुक्त होंगे लेकिन जो संकट है, वह सरकार का ही नहीं, समाज का है. एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से हमें डर के आगे जीत को सामने रखना होगा.

फूलबाई सिंह : अधूरी पढ़ाई से सामाजिक नेतृत्व तक

प्रेरक यात्रा

अजमत

लेखक सामाजिक कार्यकर्ता हैं।

फूलबाई सिंह का जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ। गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता था। कई बार उन्हें लंबा रास्ता पैदल तय करना पड़ता था। बाद में जब उच्च कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हुई तो वे रोज साइकिल से दूसरे गांव जाकर पढ़ाई करती थीं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दसवीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे छात्रावास में रहने लगीं। उस समय उनके मन में यह सपना था कि पढ़-लिखकर वे अपने जीवन में कुछ अलग करेंगी और अपने परिवार तथा समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगी। लेकिन जीवन ने उनके लिए एक अलग रास्ता तय कर रखा था। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान ही पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनकी शादी हो गई और उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई।

मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के छोटे से गांव करौंदा की रहने वाली फूलबाई सिंह कभी घर की चौखट और पारिवारिक जिम्मेदारियों तक सीमित रहती थीं। आज वे गांव-गांव जाकर लोगों को उनके अधिकारों, पोषण और शिक्षा के बारे में जागरूक कर रही हैं। उनकी कहानी सिर्फ एक महिला की व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव की कहानी है जो धीरे-धीरे ग्रामीण समाज में आकार ले रहा है- जहां महिलाएं अब केवल घर की जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि समाज के निर्माण में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

फूलबाई सिंह का जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ। गांव में प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर स्कूल जाना पड़ता था। कई बार उन्हें लंबा रास्ता पैदल तय करना पड़ता था। बाद में जब उच्च कक्षाओं में पढ़ाई शुरू हुई तो वे रोज साइकिल से दूसरे गांव जाकर पढ़ाई करती थीं।

कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और दसवीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी की। आगे की पढ़ाई के लिए वे छात्रावास में रहने लगीं। उस समय उनके मन में यह सपना था कि पढ़-लिखकर वे अपने जीवन में कुछ अलग करेंगी और अपने परिवार तथा समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगी। लेकिन जीवन ने उनके लिए एक अलग रास्ता तय कर रखा था। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान ही पारिवारिक परिस्थितियों के कारण उनकी शादी हो गई और उनकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई।

शादी के बाद उनका जीवन गांव की अन्य महिलाओं की तरह घर और परिवार की जिम्मेदारियों के इर्द-गिर्द घूमने लगा। घर का काम, खेती-बाड़ी और बाद में बच्चों की परवरिश–इन सबके बीच उनका अधिकतर समय बीतने लगा। कई बार उन्हें महसूस होता था कि पढ़ाई अधूरी रह जाने से उनके जीवन के कुछ सपने अधूरे रह गए हैं, लेकिन उस समय उन्हें यह समझ नहीं आता था कि वे अपने जीवन की दिशा कैसे बदल सकती हैं।

फूलबाई के जीवन में बदलाव की शुरुआत एक छोटे से अनुभव से हुई। एक दिन गांव में विकास संवाद समिति के कुछ साथी बच्चों और किशोरियों के साथ खेल और सीखने की गतिविधियां कर रहे थे। फूलबाई पास बैठकर यह सब देख रही थीं। बच्चों की भागीदारी, उनके उत्साह और सीखने के माहौल ने फूलबाई को प्रभावित किया। धीरे-धीरे उन्होंने उन साथियों से बातचीत शुरू की और यह समझने लगीं कि समाज में बदलाव के लिए समुदाय के साथ मिलकर काम किया जा सकता है।

इसके बाद फूलबाई ने गांव की महिलाओं को साथ लेकर एक महिला समूह बनाने की पहल की। शुरुआत में यह काम आसान नहीं था। कई महिलाओं को घर से बाहर आकर बैठकों में शामिल

होने में झिझक होती थी। लेकिन धीरे-धीरे महिलाएं समूह की बैठकों में आने लगीं और अपने जीवन से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने लगीं। इन बैठकों में फूलबाई की भूमिका महत्वपूर्ण होती गई। वे महिलाओं को बैठक के लिए बुलातीं, चर्चा को आगे बढ़ातीं और बैठकों की कार्यवाही लिखतीं।

लंबे समय बाद उन्हें फिर से पढ़ने-लिखने का मौका मिला और इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। इसी प्रक्रिया में उनके भीतर नेतृत्व की क्षमता भी विकसित होने लगी।

कुछ समय बाद उन्हें विकास संवाद समिति के साथ सामुदायिक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का अवसर मिला। यह उनके जीवन का एक नया अध्याय था। इस भूमिका में उन्हें आसपास के कई गांवों में जाकर लोगों से मिलना, उनकी समस्याओं को समझना और उन्हें सरकारी योजनाओं तथा सेवाओं से जोड़ने का काम करना था।

फूलबाई ने तय किया कि अगर उन्हें अपने काम को ईमानदारी से करना है तो उन्हें खुद ही वाहन चलाना सीखना होगा। उन्होंने हिम्मत जुटाई और कुछ ही समय में गाड़ी चलाना सीख लिया। इसके बाद वे अकेले ही दूर-दूर के गांवों में जाकर लोगों से मिलने लगीं। यह उनके जीवन में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

सामुदायिक कार्य करते हुए फूलबाई को शिक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक समझ में आने लगा। उन्होंने महसूस किया कि अगर वे अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी तो समुदाय के साथ और बेहतर तरीके से काम कर पाएंगी। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। घर की जिम्मेदारियों और सामाजिक कार्य के साथ पढ़ाई जारी रखना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी।

आखिरकार उन्होंने सामाजिक कार्य में स्नातक (बीएसडब्ल्यू) की पढ़ाई पूरी कर ली। इसी दौरान फूलबाई सिंह का जुड़ाव 'संविधान मेरी पहचान' कार्यक्रम से हुआ। इस पहल के माध्यम से उन्होंने संविधान के मूल्यों को समझना और उसे समाज के बीच पहुंचाने का काम शुरू किया।

आज वे एक संविधान फेलो के रूप में समुदाय के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वे गांवों में लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देती हैं और ग्राम सभा में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करती हैं।

फूलबाई सिंह का सपना है कि गांव की हर महिला जागरूक बने, अपने अधिकारों को समझे और आत्मनिर्भर होकर अपने जीवन के फैसले खुद लेने की ताकत हासिल करे। वे चाहती हैं कि ग्रामीण महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सम्मानजनक जीवन की बुनियादी सुविधाओं तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करें और अपने नेतृत्व से समाज में एक नई पहचान बनाएं।

कतारों में खड़ी रसोई, दावों में खड़ी सरकार

गैस संकट

डॉ. नरेश गौतम

सहायक प्रोफेसर, समाज कार्य विभाग, एसआरयू, रायपुर

भारत में एलपीजी अब केवल एक ईंधन नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की दैनिक जरूरत का हिस्सा बन चुकी है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार देश में लगभग 32.94 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें से 10 करोड़ से अधिक परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। यही कारण है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में शामिल हो चुका है। इतनी बड़ी आबादी की रसोई जब किसी एक ऊर्जा स्रोत पर निर्भर हो, तो उसकी आपूर्ति में थोड़ी-सी भी अनिश्चितता सीधे सामाजिक और राजनीतिक चिंता का कारण बन जाती है। समस्या यह है कि भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। देश में एलपीजी की खपत लगभग 33 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुँच चुकी है और इसका बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। इस आयात का लगभग 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से आता है। इसलिए उस क्षेत्र में होने वाला कोई भी राजनीतिक या सैन्य तनाव सीधे भारत की रसोई तक असर डालता है।

भारत सरकार ने हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को सक्रिय करते हुए एलपीजी और सीएनजी को आवश्यक वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। सामान्यतः यह कानून तभी लागू किया जाता है जब किसी जरूरी वस्तु की कमी होने लगे या उसकी कालाबजारी, अनियमित मूल्य वृद्धि हो रही हो। इसलिए यह कदम केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि देश की ऊर्जा आपूर्ति को लेकर समस्या है। पिछले कुछ दिनों से देश के कई हिस्सों में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर खबरे सामने आ रही हैं। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं और सीएनजी स्टेशनों पर भीड़ और अफरा तफरी मची है। ऐसे में एलपीजी और सीएनजी को आवश्यक वस्तु घोषित करना यह बताता है कि सरकार वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करना चाहती है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि यदि स्थिति सामान्य थी, जैसा कि सरकार दावा कर रही थी, तो फिर अचानक इस तरह का प्रशासनिक कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी?

भारत में एलपीजी अब केवल एक ईंधन नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों की दैनिक जरूरत का हिस्सा बन चुकी है। संसद में दी गई जानकारी के अनुसार देश में लगभग 32.94 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनमें से 10 करोड़ से अधिक परिवार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं। यही कारण है कि भारत आज दुनिया के सबसे बड़े एलपीजी उपभोक्ताओं में शामिल हो चुका है। इतनी बड़ी आबादी की रसोई जब किसी एक ऊर्जा स्रोत पर निर्भर हो, तो उसकी आपूर्ति में थोड़ी-सी भी अनिश्चितता सीधे सामाजिक और राजनीतिक चिंता का कारण बन जाती है। समस्या यह है कि भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। देश में एलपीजी की खपत लगभग 33 मिलियन टन प्रतिवर्ष तक पहुँच चुकी है और इसका बड़ा हिस्सा आयात से पूरा होता है। इस आयात का लगभग 85 से 90 प्रतिशत हिस्सा पश्चिम एशिया के देशों से आता है। इसलिए उस क्षेत्र में होने वाला कोई भी राजनीतिक या सैन्य तनाव सीधे भारत की रसोई तक असर डालता है।

वर्तमान संकट की पृष्ठभूमि भी इसी क्षेत्र से जुड़ी है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और समुद्री मार्गों पर असुरक्षा के कारण ऊर्जा आपूर्ति को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। विशेष रूप से Strait of Hormuz को विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्ग माना जाता है, जहाँ से वैश्विक ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। यदि यह मार्ग प्रभावित होता है तो भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर उसका प्रभाव तुरंत दिखाई देता है। भारत के ऊर्जा आयात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर आता है। यहाँ सबसे गंभीर प्रश्न सरकार की विश्वसनीयता का है। कुछ

ही सप्ताह पहले सरकार की ओर से यह दावा किया गया था कि देश में गैस या पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर कोई संकट नहीं है और यदि Strait of Hormuz प्रभावित भी होता है तो भारत पर उसका विशेष असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब एलपीजी और सीएनजी को आवश्यक वस्तु घोषित करना यह संकेत देता है कि वास्तविक स्थिति उतनी सहज नहीं है जितनी जनता को बताई जा रही थी। दरअसल ऊर्जा संकट केवल अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का परिणाम नहीं होता। कई बार घरेलू नीतियाँ भी प्रभावी होती है साथ ही भंडारण क्षमता, आयात के स्रोतों की विविधता और कूटनीतिक रणनीति भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी देश के पास पर्याप्त भंडारण क्षमता नहीं हो, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को पर्याप्त बढ़ावा न मिला हो, या आयात के स्रोत सीमित हों, तो वैश्विक संकट जल्दी घरेलू संकट में बदल जाता है। देश की बिडम्बना है कि ऊर्जा सुरक्षा को अभी भी दीर्घकालिक रणनीति की तरह नहीं बल्कि तात्कालिक प्रबंधन की तरह देखा जाता है। संकट सामने आने के बाद कानून लागू करना और नियंत्रण बढ़ाना आसान उपाय है, लेकिन यह नीति-निर्माण की दूरदर्शिता का विकल्प नहीं हो सकता।

इतिहास पर यदि नजर डाले तो हमें पता चलता है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का सबसे बड़ा बोझ आम लोगों पर ही पड़ता है। द्वातीय विश्व युद्ध के दौरान यूरोप और एशिया के कई देशों ने भुखमरी और लाचारी देखी है। जर्मनी के सनकी तानाशाह ने अपने देश को युद्ध में धकेल दिया परिणाम क्या हुआ। पूरा देश राख़ और खंडहर में तब्दील होगया। इसी तरह हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमबारी का परिणाम बताता है कि युद्ध का अंत अक्सर मानवीय त्रासदी में होता है, जिसका असर कई पीढ़ियों तक बना रहता है। वैश्विक संघर्ष केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका सीधा असर भोजन, पानी और ऊर्जा जैसी बुनियादी जरूरतों पर भी पड़ता है और ऊर्जा सुरक्षा केवल तात्कालिक उपायों से सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसके लिए दीर्घकालिक नीतियों की आवश्यकता होती है। एलपीजी और सीएनजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाना यह दर्शाता है कि सरकार स्थिति को गंभीरता से देख रही है। लेकिन केवल कानून लागू कर देना पर्याप्त नहीं है। असली प्रश्न यह है कि क्या सरकार ऊर्जा सुरक्षा को लेकर दीर्घकालिक और पारदर्शी नीति बनाने के लिए तैयार है, या फिर हर संकट के समय केवल तात्कालिक उपायों, या आत्मनिर्भरता की बयानबाजी से काम चलाया जाएगा। क्योंकि विकसित भारत का सपना केवल नारों और हवाबाजी से नहीं, बल्कि मजबूत नीतियों, पारदर्शी शासन, दूरदर्शी योजना और अंतोदय से ही साकार किया जा सकता है।

'विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए'

" Mantra of Success " में युवा- प्रतिभावान चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) प्राची अग्रवाल ने बताए मोटिवेशनल टिप्स

ऐतिहासिक राजा भोज की नगरी ने कई प्रतिभाओं को जन्मा हैं। देश और प्रदेश के पटल पर अपनी प्रतिभा से इस पावन धरा को गौरवान्वित किया है अनेक युवाओं ने। ऐसी ही एक प्रतिभासंपन्न बिटिया प्राची अग्रवाल ने बहुत ही कम उम्र में चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) बन यह जता दिया था कि बेटियां कहीं भी कमतर नहीं है। चार्टर्ड एकाउंटेंट (सीए) के रूप में कैरियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए वह यूथ आइकॉन है।

कॉलम "Mantra of Success" के लिए अपनी सफलता का राज बताते हुए मोटिवेशनल टिप्स देते हुए कहती हैं 'विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए' सफलता निरंतर प्रयासों से ही मिलती है इसलिए कभी अपना फोकस ना खोए।

यूथ के लिए संदेश ...

एपीजे अब्दुल कलाम 'अपने हौसलों को ये मत बताओ की परेशानी कितनी बड़ी है अपनी परेशानियों को ये बताओ की हौसले कितने बुलंद हैं'।

मैं भी यूथ को ये ही बोलना चाहूँगी कि लाइफ में मुश्किलें तो आयेंगी ही उनसे डरना या लड़ना हमारे हाथ में होता है। इसलिए कभी परेशानियों से हारों मत बस आगे बढ़ते रहो, राहें खुद ब खुद बनती जाएंगी। असफलता से डरना नहीं है सीखना है। इसे अपना मंत्र बनाओ और बढ़ते जाओ।

सफल सीए बनने के लिए खूब पढ़ते रहें...- मैंने अपनी सीए की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मैं धार से ही काम कर रही हूँ। आज मुझे प्रैक्टिस करते हुए 5 वर्ष से अधिक हो गए है। में अपने इस फ़ैसले से बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। सीए एक ऐसा क्षेत्र है जिसमे आप पढ़ना बंद नहीं कर सकते हो। आपको निरंतर कुछ नया पढ़ना और सीखना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए।

हौसलों की उड़ान...

मैंने अपनी 12वीं तक शिक्षा धार के श्री सी के चंदेल स्कूल से की है। उसके बाद सीए की तयारी के लिए में इंदौर चली गई थी। इंदौर में विभिन्न कोचिंग्स से पढ़ कर मैंने सीए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं अपने आपको भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे बहुत अच्छे शिक्षकों से पढ़ने का मौक़ा मिला। मेरे सीए बनने में मेरे परिवार का साथ मेरे लिए महत्वपूर्ण रहा, उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

बतौर सीए संदेश - हर किसी को बुनियादी वित्तीय ज्ञान होना ही चाहिए - बतौर सीए वितीय जागरूकता का संदेश देना चाहूँगी। मेरे अनुसार हर किसी को बुनियादी वित्तीय ज्ञान होना ही चाहिए। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो बिना हिचके अपने सीए से संपर्क कर लेना चाहिए।

गैस संकट और महंगाई पर बैतूल में कांग्रेस ने किया बड़ा प्रदर्शन

महंगाई, गैस संकट और ट्रेंचिंग ग्राउंड घोटाले के विरोध में सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता

बैतूल। देश में बढ़ती महंगाई, एलपीजी गैस सिलेंडरों की किल्लत और स्थानीय स्तर पर ट्रेंचिंग ग्राउंड घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बैतूल में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी बैतूल के नेतृत्व में 13 मार्च को जिला उद्योग केंद्र के सामने धरना देकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। सुबह 11 बजे जिला उद्योग केंद्र के सामने आयोजित इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष निलय विनोद डागा, प्रदेश सचिव समीर खान और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष राजकुमार दीवान ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल हुईं। धरने के बाद कांग्रेस नेताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई और गैस सिलेंडरों की किल्लत को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने खाली गैस सिलेंडर और भट्टी पर चाय की गंजी रखकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के माध्यम से यह संदेश देने की कोशिश की गई कि रसोई गैस के

दाम बढने और सिलेंडरों की कमी के कारण आम लोगों की रसोई पर संकट खड़ा हो गया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा ने कहा कि जिस गैस सिलेंडर को सरकार ने कभी उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीबों तक पहुंचाने का दावा किया था, आज वही सिलेंडर आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। श्री डागा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की गलत विदेश नीतियों के कारण देश में ईंधन संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक संकट के दौर में भारत सरकार की रणनीति पूरी तरह विफल साबित हो रही है। इसका सीधा असर देश में एलपीजी गैस की उपलब्धता और कीमतों पर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि सरकार को पहले से स्थिति का आकलन कर कदम उठाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

लोग कतारों में, सरकार बयानबाजी में- धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश के कई हिस्सों में लोग गैस सिलेंडर के लिए कतारों में खड़े होने को मजबूर हैं, लेकिन सरकार इस संकट को स्वीकार करने के बजाय केवल बयानबाजी कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि आम जनता महंगाई से जूझ रही है और सरकार इस मुद्दे पर ठोस समाधान देने में विफल साबित हो रही है। कांग्रेस नेताओं ने इस प्रदर्शन के माध्यम से बैतूल के ट्रेंचिंग ग्राउंड से जुड़े कथित घोटाले की निष्पक्ष जांच की भी मांग उठाई। उनका कहना था कि स्थानीय स्तर पर कई जनसमस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं ले रही है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष निलय डागा, प्रदेश कांग्रेस सचिव समीर खान, नेता प्रति पक्ष नगर पालिका बैतूल राजकुमार दीवान संगठन, महासचिव ब्रज भूषण पांडे, लोकेश पगारिया प्रशांत मरोठी सहित सैकड़ो कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।

चिकित्सकों के संवेदनशील व्यवहार से मरीजों की आधी तकलीफ हो जाती है दूर : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

उप मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज शहडोल के ब्लड सेंटर का किया शुभारंभ

भोपाल। चिकित्सक धरती पर भगवान के स्वरूप होते हैं। चिकित्सक मरीजों को नया जीवन देने का कार्य करते हैं। मरीज अस्पताल में खुशियां बांटने नहीं आते, बल्कि अपनी मजबूरी और जीवन की नई उम्मीदों के साथ आते हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग का अमला पूरी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करे तो अस्पताल आने वाले मरीजों की आधी तकलीफ अपने-आप दूर हो जाती है और उन्हें जीवन जीने का संबल भी मिलता है। उक्त विचार उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने आज शासकीय बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज एवं चिकित्सालय शहडोल में ब्लड सेंटर के शुभारंभ अवसर पर व्यक्त किए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ब्लड सेंटर का शुभारंभ शहडोल संभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इससे संभाग के मरीजों को सरलता और सहजता से रक्त उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि शासकीय बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थी बेहतर शिक्षा ग्रहण कर देश और समाज की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दें।

निर्माणाधीन विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ करें पूर्ण : शुक्ल

उप मुख्यमंत्री एवं शहडोल जिले के प्रभारी मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कलेक्टर कार्यालय के विराट सभागार में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे निर्माणाधीन विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागों द्वारा संचालित विकास कार्यों को समय-सीमा में प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराया जाए, ताकि आमजन को उनका लाभ मिल सके। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में प्राप्त निवेश प्रस्तावों पर भी चर्चा करते हुए एमपीआईडीसी एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर प्रस्तावित निवेशकों को शीघ्र भूमि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रभावशाली उपस्थिति - केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने दिया राष्ट्रीय संबोधन

महिला नेतृत्व वाले विकास और लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई

धार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में आयोजित महिला स्थिति आयोग (सीएसडब्ल्यू-70) के 70वें सत्र की आम चर्चा के दौरान भारत की ओर से राष्ट्रीय संबोधन दिया। इस अवसर पर विश्व के अनेक देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए और लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की वैश्विक प्रतिबद्धता को

दोहराया। अपने संबोधन में सावित्री ठाकुर ने महिला नेतृत्व वाले विकास की दिशा में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत का विकास दर्शन 'सबका साथ, सबका विकास' समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है।

उन्होंने बताया कि देश में लगभग 90 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 10 करोड़ से अधिक महिलाएं जमीनी स्तर पर नेतृत्व और उद्यमिता को बढ़ावा देते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि अटल इन्क्यूबेशन केंद्रों के तहत समर्थित 1,000 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं, जबकि 8 लाख से अधिक महिला निदेशक देश की सक्रिय कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे लैंगिक डिजिटल असमानता को कम करने में सहायता मिली है।

रसोई गैस सिलेंडर की घर तक आपूर्ति सुनिश्चित की जाए : भाकपा

भोपाल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रसोई गैस सिलेंडर के संकट पर गहरी चिंता व्यक्त कर इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए गोदाम से देना बन्द कर उपभोक्ता के घर ही आपूर्ति की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। भाकपा मध्य प्रदेश के राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की लापरवाही ,अदूरदर्शिता के कारण ही रसोई गैस सिलेंडर का संकट जारी है। कालाबाजारी बढ़ रही है और इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की है। रसोई गैस सिलेंडर की एजेंसी के मालिक बुकिंग के माध्यम से सिलेंडर की उपभोक्ता के घर आपूर्ति बन्द कर सीधे गोदाम से सिलेंडर दे रहे हैं और मनमाने दाम वसूल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इसे रोकने हेतु कोई भी प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। इससे स्थानीय स्तर पर रसोई गैस एजेंसी के मालिकों और जिला प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत की आशंका बनी हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य सरकार से मांग है कि गोदाम से सिलेंडर देना बन्द कर उपभोक्ता को सीधे घर पर ही आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।अन्यथा स्थानीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

18 साल बाद पारदी दंपती हत्याकांड में फैसला

पारदी हत्याकांड में पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, राजा पवार सहित 14 आरोपी बरी

बैतूल/मुलताई। जिले के बहुचर्चित पारदी दंपती हत्याकांड में लगभग 18 वर्षों बाद अदालत का फैसला आ गया है। भोपाल स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री एवं विधायक सुखदेव पांसे तथा जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार सहित कुल 14 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। शुक्रवार को सुनाए गए इस फैसले के साथ ही करीब दो दशकों से न्यायालय में लंबित यह बहुचर्चित मामला समाप्त हो गया। यह मामला वर्ष 2008 में बैतूल जिले के मुलताई क्षेत्र के चौथिया गांव का है। उस समय पारदी समुदाय के डेरे में हिंसा और आगजनी की घटना सामने आई थी। घटना के बाद बोंदर पारदी और उनकी पत्नी के शव गांव के एक कुएं से बरामद किए गए थे। इस दोहरे हत्याकांड ने उस समय पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की थी। जांच के दौरान तत्कालीन कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री

सुखदेव पांसे, वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष राजा पवार सहित कुल 16 ग्रामीणों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी सुनवाई भोपाल स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में स्थानांतरित की गई, जहां यह प्रकरण लगभग 18 वर्षों तक विचाराधीन रहा।

लंबे समय तक चली न्यायिक प्रक्रिया- इस दौरान अदालत में कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए और मामले से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच की गई। हालांकि लंबी सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मृत्यु हो गई, जिसके चलते अंतिम निर्णय के समय अदालत ने 14 आरोपियों के विरुद्ध ही फैसला सुनाया। शुक्रवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सभी 14 आरोपियों को दोषमुक्त करार देते हुए बरी कर दिया।

18 वर्षों से लंबित बहुचर्चित मामला समाप्त- आरोपियों की ओर से अधिवक्ता वी.के. सक्सेना और संजय रावत ने अदालत में पैरवी की। फैसले के बाद उन्होंने कहा कि न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय दिया है। वहीं फैसले के बाद आरोपियों के समर्थकों ने इसे सत्य की जीत बताते हुए खुशी जाहिर की और राहत की सांस ली।

पुलिस ने बुजुर्ग के 17,000 रुपये वापस दिलाए

बैतूल। पुलिस ने एक बुजुर्ग व्यक्ति के गिरे हुए 17,000 रुपये वापस दिलाकर सराहनीय कार्य किया गया। दरअसल 11 मार्च को शाम करीब 6 बजे ओझा उईके उम्र 55 वर्ष, निवासी चारसी थाना बैतूल बाजार द्वारा सूचना दी गई कि वह पिछले 3 माह से महाराष्ट्र में मजदूरी कर वापस आया था, जहां उसे मजदूरी के रूप में 17,000 रुपये प्राप्त हुए थे। उक्त राशि बडोरा चौक आठनेर रोड के पास कहीं जेब से गिर गई। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी बैतूल बाजार निरीक्षक अंजना धुर्वे द्वारा तत्काल पुलिस बल मौके

पर भेजकर आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखने निर्देश दिए गए। सीसीटीवी फुटेज जांच के दौरान एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा रुपये उठाते हुए दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उस व्यक्ति की पहचान के लिए उसके आने-जाने के पूरे रूट का पता लगाकर लगभग 13 स्थानों के सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाई गई। पुलिस के लगातार प्रयासों के बाद अज्ञात व्यक्ति की पहचान कर उसे थाना बैतूल बाजार बुलवाया गया, जिसने काफी मशक्कत के बाद रुपये उठाने की बात आखिरकार स्वीकार की। उक्त व्यक्ति से बुजुर्ग व्यक्ति के जेब से गिरे हुए 17,000 रुपये बुजुर्ग के परिजनों की उपस्थिति में वापस दिलवाए गए। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी बैतूलबाजार निरीक्षक अंजना धुर्वे, आरक्षक अनिरुद्ध यादव, आरक्षक नितिन चौहान, प्रधान आरक्षक मुकेश पवार एवं थाना बैतूल बाजार पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

समूचा नगर पानी के लिए परेशान, कांग्रेसियों ने सौंपा ज्ञापन, इन्दौर जैसी घटना की आशंका जताई

सोहागपुर। बड़े-बड़े दावे करने वाला सोहागपुर विधानसभा का मुख्यालय इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहा है। इससे करीबन नगर 25 हजार वाशिंदों पर पीने के पानी के लिए दो दो हाथ करना पड़ रहा है। हुआ यूं कि विगत दिनों से नर्मदा जल परियोजना की जल प्रदाय सप्लाई ठप्प हो गई। इससे हालात खराब हो गए। जिससे नगर पंचायत परिषद को अपनी पुरानी जल प्रदाय को चालू करना पड़ा। फिर भी कई वार्डों में पानी की किल्लत रही। हालांकि नगर पंचायत परिषद ने टेंकरों से जल सप्लाई कराई। लेकिन यह जल सप्लाई अपर्याप्त रही।

इधर अंबेडकर वार्ड के पूर्व पार्षद मोहन कहार ने अपनी राशि से हेन्डपंप सुधरवा कर वार्डवासियों को कुछ राहत पहुंचाई। इधर आज ब्लाक कांग्रेस एवं नगर कांग्रेस ने नगर की विकराल पानी की समस्या को लेकर अनुविभागीय अधिकारी के नाम नायब

तहसीलदार रंजीतसिंह को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कहा गया है कि नगर परिषद सोहागपुर द्वारा जल आपूर्ति की नर्मदा जल योजना कुछ समय से बंद है। जिससे भीषण गर्मी में समूचे पानी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। जिससे जबकि पानी जीवन चलाने के लिये सबसे महत्व बिना पानी के कुछ भी किया जाना संभव नहीं है। लेकिन नगर पंचायत परिषद के द्वारा जिस पाईप लाइन से जो पानी आ रही है।वह पूर्णतः दूषित है। इस पानी में कीड़े निकल रहे हैं। जिससे नगर में गंभीर बीमारी फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस मामले की जांच करके जल आपूर्ति जल्द शुरू की जाए। अन्यथा कहीं इन्दौर जल प्रदाय से होने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो जाए। इस अवसर पर ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष सुधीर ठाकुर, नगर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत जायसवाल, वकील मंगलसिंह रघुवंशी गजेन्द्र सिंह चौधरी,प्रकाश मालवीय ,नीरज चौधरी,धनराज बलवंशी चुन्नीलाल मुगदल, नीतिन चौरसिया,अर्पित तिवारी, वकील कार्तिक शर्मा, इरफान खान, समाजसेवी गणेश अहिरवार आदि उपस्थित थे।

मढ़ई, पचमढ़ी में सिंगल यूज पर प्रतिबंध

सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई की पर्यटन रणनीति की समीक्षा, स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक संपन्न

सोहागपुर। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई में स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में विधायक पिपरिया ठाकुरदास नागवंशी, सीसीएफ अशोक कुमार, कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, कलेक्टर बैतूल नरेंद्र सूर्यवंशी, फील्ड डायरेक्टर श्रीमती राखी नंदा, एसडीएम पिपरिया आकिप खान, संजय लिडवानी पचमढ़ी, कमल धूत पचमढ़ी, अरूण शर्मा, दिनेश शर्मा अधिकारीगण जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

बैठक में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों, पर्यावरण संरक्षण तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार के अवसरों को लेकर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। जिसमें में वन्यप्राणी गलियारों के महत्व एवं पारिस्थितिकी सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की सीमा के निकट भवन एवं अन्य अधोसंरचनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक मापदंड निर्धारित किए जाने पर समिति ने सर्वसम्मति व्यक्त की। इसके साथ ही संरक्षित क्षेत्र की सीमा के निकट पर्यटन सुविधाओं के पर्यावरण के अनुकूल विस्तार, पर्यटन से रोजगार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा इसके संभावित दुष्प्रभावों के न्यूनीकरण एवं पुनर्संयोजन के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

बैठक के अध्यक्ष कमिश्नर श्री तिवारी ने निर्देश दिए कि पचमढ़ी, मढ़ई सहित संभाग के अन्य संरक्षित क्षेत्रों में सिंगल यूज पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाएं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों एवं स्थानीय निवासियों को प्लास्टिक बोतलों तथा सिंगल यूज पॉलिथीन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाना आवश्यक है। इसके लिए होटल संचालकों, टैक्सी एसोसिएशन एवं अन्य संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर जनजागरूकता बढ़ाई जाए। आपने कलेक्टरों को भी इस दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उक्त बैठक यह भी सहमति बनी कि होटल, लॉज एवं टूर संचालकों की गतिविधियों का नियमित अनुश्रवण किया जाए ।ताकि पर्यटकों के भ्रमण से वन्यप्राणियों को किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। इसके साथ स्थानीय समुदाय के सदस्यों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण के अनुकूल और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने पर भी मंथन किया गया। बैठक में टाइगर रिजर्व तथा आसपास के क्षेत्रों में पर्यटन विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर स्थानीय प्रशासन और राज्य शासन को उपयुक्त प्रस्ताव भेजने का भी विचार किया गया।

विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं: अपर मुख्य सचिव श्री शुक्ला

जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य और शिक्षा योजनाओं की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए निर्देश

रायसेन (निप्र)। अपर मुख्य सचिव श्री संजय कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में बुधवार को भोपाल संभाग की विकास योजनाओं और शासकीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर आयुक्त कार्यालय के सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी, विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल श्री भगवानदास सबनानी, शमशाबाद विधायक श्री सूर्यप्रकाश मीणा, नरसिंहगढ़ विधायक श्री मोहन शर्मा एवं बैरसिया विधायक श्री विष्णु खत्री सहित अन्य जिलों से सभी विधानसभाओं के विधायकगण भी वीसी के माध्यम से जुड़े।

इसके साथ ही रायसेन कलेक्टर श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर्स, जिला पंचायत सीईओ तथा संबंधित विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री शुक्ला ने स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नल-जल योजना और जल जीवन मिशन सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की तथा योजनाओं के समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए।

स्वास्थ्य, शिक्षा और आंगनवाड़ियों की सघन निगरानी

श्री शुक्ला ने कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य सेवाओं, विद्यालयों और आंगनवाड़ियों के संचालन की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्कूलों की व्यवस्थाओं पर सतत निगरानी रखने तथा किसी भी प्रकार की कमी या अनियमितता पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

पेयजल आपूर्ति और जनप्रतिनिधियों से समन्वय

आगामी ग्रीष्मकाल को देखते हुए श्री शुक्ला ने समूह पेयजल योजनाओं को समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो सके। उन्होंने कलेक्टर्स से कहा कि जनप्रतिनिधियों, विशेषकर विधायकों के साथ निरंतर संवाद और समन्वय बनाए रखें तथा उनके द्वारा उठाई गई जनसमस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और समय-सीमा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार्य नहीं होगा। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अधोसंरचना और नगरीय विकास पर जोर

बैठक में अमृत-2.0 योजना के अंतर्गत किए जा रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य पूर्ण होने के बाद सड़कों को जीर्ण-शीर्ण अवस्था में न छोड़ा जाए और उनका समय पर संधारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नगरों के बढ़ते विस्तार को ध्यान में रखते हुए शहरों की बाहरी सीमाओं पर बहुद्देश्यीय विकास परियोजनाओं का निर्माण किया जाए, जिससे शहरी विकास को नियोजित स्वरूप मिल सके।

विभागीय समन्वय और प्रशासनिक सुदृढ़ता पर बल

अपर मुख्य सचिव श्री शुक्ला ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों के पास दोहरा प्रभार है, वे निर्धारित दिवसों पर संबंधित कार्यस्थलों पर उपस्थित रहकर कार्यों की नियमित समीक्षा करें, ताकि विकास कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए। साथ ही, बांधों के लिए अधिग्रहित भूमि का शीघ्र नामांतरण संबंधित विभागों के नाम करने के निर्देश भी दिए गए।

संक्षिप्त समाचार

गांव में आटा चक्की और किराना दुकान की शुरुआत से एक ग्रामीण परिवार का बदला जीवन

विदिशा (निप्र)। आजीविका मिशन द्वारा स्व सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं भी अब अपने परिवार को आगे बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में पीछे नहीं है। सिरोंज तहसील के ग्राम भौंरा में निवासरत श्रीमती राजकुमारी अहिरवार घर की महिला सदस्य होने के बावजूद और ग्राम में निवास करने के बाद भी लव कुश स्व सहायता समूह से जुड़ीं और लोन राशि प्राप्त कर घर में ही आटा चक्की और किराना दुकान शुरू कर उन्होंने अपनी मासिक आय 12 हजार से अधिक कर ली है। समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है और उनके बच्चे अच्छे स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं परिवार खुशहाल जिंदगी जी रहा है। श्रीमती राजकुमारी अहिरवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक हो गई है और वह लखपति दीदी की श्रेणी में भी शामिल हो गई हैं। श्रीमती राजकुमारी अहिरवार ने बताया कि समूह से जुड़ने के पूर्व की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। समूह से जुड़ने के पूर्व मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी उनकी वार्षिक आय 45 हजार रूपए ही थी। वर्तमान में समूह से जुड़ने के पश्चात श्रीमति राजकुमारी बाई ने समूह में बैठक एवं बचत की 6 माह बाद उन्होंने सीआईएफ से 10 हजार एवं सीसीएल से 1 लाख की ऋण राशि प्राप्त की और मुद्रा लोन से 50 हजार का ऋण राशि प्राप्त की जिससे उन्होंने आटा चक्की एवं किराना दुकान की गतिविधि प्रारंभ की। उनकी मेहनत रंग लाई और अब उनकी मासिक आय 12 हजार 500 रुपये तक हो गई है। समूह से जुड़ने के बाद श्रीमति राजकुमारी बाई ने परिवार के साथ मजदूरी छोड़कर बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना प्रारंभ किया जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बदलाव आया है।

कलेक्टर ने लंबित आवेदनों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने आज विभिन्न विभागों में लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से अपने कार्यालयों में उपस्थित रहकर आमजन के आवेदनों का त्वरित समाधान करें। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कल से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति की क्रॉस मॉनिटरिंग की व्यवस्था लागू की जाएगी, जिससे कार्यालयों में अनुशासन और कार्य की गति बनी रहे। बैठक में कलेक्टर ने महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित विषयों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिले के सभी कुपोषित बच्चों को अनिवार्य रूप से पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) में भर्ती कराया जाए। साथ ही वहां भर्ती बच्चों को सुपोषण किट भी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उनके स्वास्थ्य में शीघ्र सुधार हो सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि जब भी वे अपने कार्यक्षेत्रों का भ्रमण करें तो आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण अवश्य करें और वहां बच्चों को मिलने वाली सेवाओं, पोषण आहार तथा व्यवस्थाओं का जायजा लें। बैठक के दौरान कलेक्टर ने खाद्य विभाग के माध्यम से किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली। उन्होंने पात्रता पर्ची के आधार पर हितग्राहियों को वितरित किए जा रहे खाद्यान्न की स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से वितरण व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो।

जिला पंचायत सीईओ ने की आजीविका मिशन के उत्पादक समूहों के कार्यों की समीक्षा

सीहोर (निप्र)। जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव ने जिला पंचायत सभाकक्ष में एनआरएलएम के जिला एवं ब्लॉक स्तरीय उत्पादक समूहों एवं सीएलएफ पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर उत्पादक समूहों के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने समूहों के बिजनेस प्लान पर भी चर्चा की। इस दौरान बताया गया कि उत्पादक समूहों के बिजनेस प्लान के अनुसार एसआरएलएम द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है। बैठक में उत्पादक समूह का व्यवसाय विकसित करने के उद्देश्य से मार्केट वेंडर मॉडल के बारे में भी जानकारी दी गई तथा जिले में उत्पादक समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति भी साझा की गई। बैठक में बताया गया कि अभी तक जिले में 34 उत्पादक समूहों के बिजनेस प्लान राज्य द्वारा स्वीकृत किए गए हैं एवं इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों से 60 लाख का टर्नओवर अर्जित किया गया है। इन सभी को देखते हुए राज्य द्वारा 96 लाख रूपये की राशि बिजनेस सपोर्ट के लिए उपलब्ध कराई गई है। इस प्रकार जिले में एनआरएलएम के अंतर्गत उत्पादक समूह कार्य कर रहे है। बैठक में जिला पंचायत सीईओ द्वारा आजीविका मिशन स्टाफ की समीक्षा के दौरान निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने, विभिन्न समूहों के बैंक बचत खाते खुलवाने एवं चक्रीय राशि आप्राप्त समूह को पात्रता अनुसार राशि मांग करने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती यादव ने उपस्थित 150 से भी अधिक समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भरता का संदेश हुए कहा कि समूह से जुड़कर महिलायें आय मूलक गतिविधियों से अपनी और अपने परिवार की आय में वृद्धि कर रही है, यह महिलाओं के लिए सम्मान और गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि अजीविका मिशन से जोड़कर अधिक से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाना शासन और प्रशासन का उद्देश्य है। बैठक में डीपीएम श्री दिनेश बरफा सहित अन्य अधिकारी एवं समूह की दीदियां उपस्थित थीं।

बाल एवं बंधक और बंधक श्रम क्षमता संवर्धन संभागीय कार्यशाला का किया गया आयोजन

नर्मदापुरम (निप्र)। बाल एवं बंधक श्रम क्षमता संवर्धन संभागीय कार्यशाला का आयोजन सांई कृष्णा रिजार्ट आई टी आई रोड नर्मदापुरम में किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि श्री अभय सिंह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्री शैलेन्द्र कौरव अध्यक्ष बाल कल्याण समिति नर्मदापुरम, श्री अमरजीत सिंह, यूनिसेफ, श्रीमती रजनी मालवीय, सहायक श्रमायुक्त नर्मदापुरम, जिला श्रम कार्यालय बैतूल एवं हरदा के अधिकारी जिला टास्क फोर्स समिति के सभी सदस्य तथा जिले के आद्यौगिक संगठन के प्रतिनधि उपस्थित रहे। कार्यशाला में बाल एवं बंधक श्रमिक अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों की जानकारी दी गई। यूनिसेफ से उपस्थित श्री अमरजीत कुमार सिंह द्वारा बाल श्रम से संबंधित स्टेट एक्शन प्लान की जानकारी दी गई तथा संभाग के समस्त जिलो की कार्ययोजना तैयार करने हेतु मार्गदर्शन दिया गया।

हार्वेस्टर मशीन से गेहूं कटाई के साथ बन रहा भूसा, नरवाई जलाने की जरूरत खत्म

नरवाई प्रबंधन के लिए किसानों को मिल रही अनुदानित मशीनें, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा

नरवाई प्रबंधन में यंत्रों के उपयोग की कलेक्टर ने की किसानों से अपील

नरवाई प्रबंधन के लिए सरकार भी दे रही यंत्रों पर अनुदान

सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरू के. के निर्देशानुसार जिले में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए कृषि विभाग द्वारा लगातार प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में किसानों को नरवाई प्रबंधन के लिए आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को अनुदान पर हार्वेस्टर एवं अन्य कृषि मशीनें उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिनकी सहायता से गेहूं की कटाई के साथ-साथ नरवाई से भूसा भी तैयार किया जा रहा है। इस तकनीक के उपयोग से किसानों को अतिरिक्त लाभ मिल रहा है तथा खेतों में नरवाई जलाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। कृषि उप संचालक श्री अशोक उपाध्याय ने बताया कि इस पहल से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि खेतों की उर्वरता भी बनी रहती है और किसानों को बेहतर नरवाई प्रबंधन का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा विभाग द्वारा किसानों को जागरूक करने के लिए लाउड स्पीकर के माध्यम से निरंतर प्रचार-प्रसार भी किया जा रहा है, ताकि जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके।

नरवाई प्रबंधन के लिए सरकार भी दे रही यंत्रों पर अनुदान : कृषकों द्वारा नरवाई को जलाने से रोकने के लिए शासन द्वारा भी कई कदम उठाये गये हैं, जिसमें प्रदेश स्तर पर 46,800 से अधिक नरवाई प्रबंधन से संबंधित कृषि यंत्र अनुदान पर वितरित करने के लिए कुल 468 करोड़ रूपये की अनुदान राशि जारी की गई है।

वर्ष 2025-26 में नरवाई प्रबंधन से संबंधित 15 फसल अवशेष सप्लाई चैन (एग्रीगेटर) स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में नरवाई प्रबंधन के लिए हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्रॉ रीपर, बेलर जैसे 07 हजार कृषि यंत्रों को अनुदान के माध्यम से वितरित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। नरवाई प्रबंधन में यंत्रों के उपयोग की कलेक्टर ने की अपीलकलेक्टर श्री बालागुरू के. ने किसानों से नरवाई प्रबंधन यंत्र अपनाने व नरवाई न जलाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि भूमि की उपजाऊ क्षमता बनाएं रखने हेतु खेतों में नरवाई नहीं जलाएं। सरकार किसानों को नरवाई प्रबंधन में उपयोग किये जाने वाले यंत्रों पर 40 से 50 प्रतिशत तक अनुदान दे रही हैं। जो किसान यंत्र नही खरीद सकते वो किराये पर लेकर उपयोग करें, इन यंत्र के उपयोग से उत्पादन भी अधिक होगा तथा लागत भी कम लगेगी। कलेक्टर ने किसानों से अपील की है कि किसान कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ लेकर अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें और पर्यावरण का संरक्षण करें।

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि विभाग द्वारा किया गया बीआरसी केंद्र का शुभारंभ

केंद्र से किसानों को मिलेंगे सस्ते जैविक उत्पाद

सीहोर (निप्र)। कृषि विभाग द्वारा इछावर तहसील के ग्राम गाजीखेड़ा में जैविक संसाधन केंद्र (बीआरसी) का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर कृषि उप संचालक श्री अशोक कुमार उपाध्याय ने किसानों को जैविक खेती के महत्व के बारे में जानकारी दी और बताया कि इस बीआरसी केंद्र के माध्यम से किसानों को जैविक उत्पाद बाजार की तुलना में कम लागत पर उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे खेती की लागत कम करने में सहायता मिलेगी। बीआरसी केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस जैविक संसाधन केंद्र की उत्पादन क्षमता 45 दिनों में लगभग 300 लीटर जैविक घोल तैयार करने की है। इस केंद्र में कुल 10 प्रकार के जैविक उत्पाद तैयार किए जाते हैं।

इसके केंद्र में किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पाद तैयार किए जाते हैं, जिनमें श्वरू2 घोल, देसी कल्प अर्क, दशपर्णी अर्क, फल अर्क, सप्तधान्य अर्क, ह्यूमिक एसिड अर्क, अमिल अर्क, जैविक माइक्रोऑर्गेनिज्म स्लरी, फुल्विक एसिड घोल एवं वायमिल अर्क शामिल हैं। ये सभी उत्पाद प्राकृतिक एवं जैविक विधियों से तैयार किए जाते हैं। इनका उपयोग करने से मृदा में लाभकारी सूक्ष्मजीवों की संख्या बढ़ती है, मृदा की संरचना एवं उर्वरता में सुधार होता है तथा पौधों को आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। साथ ही ये जैविक घोल पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं, जड़ों के विकास को मजबूत बनाते हैं और फसलों को कीट एवं रोगों से सुरक्षित रखने में भी सहायक होते हैं। इन जैविक उत्पादों के नियमित उपयोग से खेती की लागत कम होती है, रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों पर निर्भरता घटती है तथा किसानों को स्वस्थ, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन प्राप्त करने में मदद मिलती है। साथ ही यह पहल क्षेत्र में प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस बीआरसी केंद्र से क्षेत्र के लगभग 314 किसानों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ प्राप्त होगा। किसानों को यहां से जैविक घोल एवं अन्य जैविक इनपुट आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष ग्राम सेवनिया में भी जैविक संसाधन केंद्र का शुभारंभ किया गया था, जो क्षेत्र में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में उद्यानिकी विभाग के सहायक संचालक श्री जगदीश मुजाल्दा सहित अन्य अधिकारी एवं किसान उपस्थित थे।

नर्मदापुरम् संभाग के सोशल मीडिया प्रभारी बने एस सुजीत कुमार

नर्मदापुरम्। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल की सहमति से भाजपा सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक सुयश त्यागी द्वारा प्रदेश सोशल मीडिया टीम का गठन कर 13 संभाग के संभाग के प्रभारी एवं सह प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। इस टीम में एस सुजीत कुमार को नर्मदापुरम् संभाग का सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है।

सुजीत की नियुक्ति से संभाग में पार्टी की नीतियों, विचारधारा एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का डिजिटल प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। सोशल मीडिया क्षेत्र में उनकी सक्रियता और संगठन के प्रति समर्पण को देखते हुए यह जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल कार्यकाल की शुभकामनाएँ दीं। वहीं एस सुजीत कुमार ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन की अपेक्षाओं के अनुरूप पूरी निष्ठा के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे।

मुक्तिधाम की भूमि का कराया गया सीमांकन

विदिशा (निप्र)। लटेरी तहसील के ग्राम आनन्दपुर में मुक्तिधाम की भूमि को लेकर स्पष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तहसीलदार श्री हेमंत अग्रवाल की उपस्थिति में भूमि का सीमांकन कराया गया। सीमांकन की कार्यवाही के दौरान राजस्व अमले द्वारा मौके पर भूमि की सीमा निर्धारित कर ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी गई। तहसीलदार श्री हेमंत अग्रवाल ने मौके पर उपस्थित ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों एवं ग्रामीणों को मुक्तिधाम की निर्धारित भूमि की सीमा समझाई तथा भविष्य में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति से बचने के लिए सीमांकन का पालन करने के निर्देश दिए। इस दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारी, पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे।

जिले के 779 वृद्धजन अयोध्या तीर्थ यात्रा हेतु हुए रवाना विधायक डॉ चौधरी ने वृद्धजनों का रेल्वे स्टेशन पर किया स्वागत

रायसेन (निप्र)। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत रायसेन जिले के 779 तीर्थ यात्री, अनुरक्षकों के साथ 11 मार्च को भोपाल स्थित कमलापति रेल्वे स्टेशन भोपाल से ट्रेन के माध्यम से अयोध्या के लिए रवाना हुए। रायसेन जिले के तीर्थ यात्रियों को रानी कमलापति रेल्वे स्टेशन भोपाल तक ले जाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा वाहन व्यवस्था की गई थी। तीर्थ यात्रियों के लिए विकासखण्ड/तहसील स्तर पर वाहन व्यवस्था की गई, जहां से तीर्थ यात्री बसों के माध्यम से कमलापति रेल्वे स्टेशन भोपाल पहुचें। यहां सांची विधायक डॉ प्रभुराम चौधरी द्वारा तीर्थ यात्रियों को पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया गया तथा यात्रा हेतु शुभकामनाएं दी गईं। इस अवसर पर उप संचालक सामाजिक न्याय श्री मनोज बाथम सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

सड़कों के मेंटेनेंस एवं मरम्मत का कार्य सड़क निर्माण विभाग प्राथमिकता से करें:कमिश्नर

कमिश्नर ने संभाग की सड़कों के निर्माण कार्य एवं डीपीआर तथा स्वीकृति की समीक्षा की

नर्मदापुरम (निप्र)। सड़क निर्माण की डीपीआर बनाने में अधिक समय ना लगे, डीपीआर के पश्चात सड़क निर्माण का टेंडर प्राथमिकता से लगाया जाए। टेंडर के पश्चात सड़क निर्माण का कार्य भी अविलंब शुरू कर दिया जाए। सभी सड़कों की मेंटेनेंस एवं मरम्मत का कार्य अ विलंब शुरू किया जाए। उक्त निर्देश नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने बुधवार को आयोजित मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड गृह निर्माण मंडल एवं मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की संभागीय समीक्षा बैठक में दिए। प्रबंधक मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने बताया कि वर्तमान में हरदा से आशापुर सड़क का कार्य किया जाना है इसके साथ ही हरदा से खिड़कियां तक जाने वाली सड़क के मेंटेनेंस का कार्य भी किया जा रहा है।

प्रबंधक मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण ने बताया कि वर्तमान में सड़कों के रिनुवल का कार्य कर रहे हैं, कई सड़कों के निर्माण कार्य के लिए टेंडर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री मजरा टोला के अंतर्गत सड़क निर्माण के कार्यों का सर्वे किया गया है। हर जिले की प्रत्येक विधानसभा में 20 किलोमीटर तक के सड़क का निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जाना है। इसके अनुरुप नर्मदापुरम जिले में 80 किलोमीटर की सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। सोहागपुर में 14 सड़क एवं पिपरिया में 10 सड़क निर्माणाधीन है। हरदा में 40 एवं बैतूल में 100 किलोमीटर तक की रोड बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि माइनिंग के अंतर्गत कुछ सड़क आ रही है जिससे सड़क निर्माण में दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया कि कादी कला रोड व तारा रोड़ा रोड बारिश में खराब हो गई थी जिसके मेंटेनेंस का कार्य किया जाना है।

विद्युत विभाग के अधीक्षण यंत्री ने बताया कि सब स्टेशन मालाखेड़ी रायपुर, साधपुरा निभौरा में पावर स्टेशन बनने हैं। साधपुरा में एक हेक्टेयर क्षेत्र में सब स्टेशन बनाया जाएगा यहां से 25 किलोमीटर की विद्युत लाइन भी डाली जाएगी। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि ग्रीष्म ऋतु में लाइन लास ना हो विद्युत सप्लाई निर्बाध गति से चालू रहे। जहां भी ट्रांसफार्मर बंद होने की सूचना प्राप्त हो वहां पर प्राथमिकता से ट्रांसफार्मर भी बदले जाएं। बताया गया कि सोडलपुर सब स्टेशन भी इसी वर्ष कार्य करना शुरू कर देगा।

बैठक में हाउसिंग बोर्ड गृह निर्माण मंडल के ई ई ने। बताया कि बैतूल में केंद्रीय जेल का निर्माण कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में निर्माण कार्य 75% पूरा हो चुका है। 15 अगस्त को इसका विधिवत उद्घाटन किया जाएगा।

बैठक में संयुक्त आयुक्त विकास श्री नवल मीणा, उपायुक्त विकास श्री डी एन पटेल सहित सड़क निर्माण विभाग के अधिकारी गण उपस्थित रहे।

सिवनी में शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त

ब्रेकयान के पहिए पटरी से उतरे, यात्रियों में हड़कंप

सिवनी (नप्र)। शहडोल से नागपुर की ओर जा रही शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस के साथ आज एक बड़ा हादसा होने से बाल-बाल बच गया। जानकारी के अनुसार, नैनपुर से केवलारी के बीच ट्रेन के पहिए अचानक पटरी से नीचे उतर गए। पटरी से उतरते ही ट्रेन में तेज झटका महसूस हुआ, जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। इसके बाद अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई।

दोपहर साढ़े बारह बजे की घटना

यह घटना करीब दोपहर साढ़े 12 बजे की है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले नैनपुर-केवलारी के बीच शहडोल-नागपुर एक्सप्रेस के पहिए पटरी से उतर गई। गनीमत रही कि उस समय ट्रेन की रफ्तार कम थी। इसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद ट्रैक से कोच को हटाने में जुट गए।

कोई जनहानि नहीं

गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि या किसी यात्री के घायल होने की सूचना नहीं है। हादसे की जानकारी मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी और तकनीकी टीम घटना स्थल के लिए रवाना हो गई है। ट्रेन को वापस पटरी पर लाने और मार्ग को सुचारू करने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू किया जा रहा है।

नागपुर की ओर जा रही थी ट्रेन

बताया जा रहा है कि यह ट्रेन नागपुर की ओर जा रही थी। ट्रेन की गति सामान्य थी। इस दौरान जोरदार झटके के साथ ब्रेकयान के पहिए पटरी से नीचे उतर गए। अचानक हुए हादसे की वजह से यात्रियों की धड़कनें बढ़ गई।

रेलवे ट्रैक है बाधित

वहीं, इस आदेश के बाद रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित है। रेलवे की तकनीकी टीम ब्रेकयान को ट्रैक पर लाने में जुटी है। इसके बाद गाड़ी वहां से आगे बढ़ेगी तो अन्य गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो पाएगी।

प्रदेश में एजेंसियों के बाहर कतारें

50 हजार होटल-रेस्टॉरेंट में गैस खत्म होने के कगार पर, इंडक्शन-डीजल भट्टी के रेट दोगुने

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग बंद सी है। सर्वर डाउन है, इसलिए लोग बुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। वेटिंग 7 से 8 दिन तक पहुंच गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेशभर में गैस एजेंसियों और गोदामों के बाद सुबह से लोगों की भीड़ लगी हुई है। कुछ शहरों से सिलेंडर की कालाबाजारी के आरोप भी लगे हैं।

इधर, मार्केट में इंडक्शन और डीजल भट्टी की कीमतें बढ़ी हैं। भोपाल में इंडक्शन की बिक्री 7 गुना तक बढ़ गई है। वहीं, प्रदेश में 50 हजार होटल-रेस्टॉरेंट में गैस खत्म होने के कगार पर है। सतना के 86 लोगों ने सिलेंडर नहीं मिलने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की है। उज्जैन में एक प्राइवेट अस्पताल की कैंटीन में डीजल भट्टी से खाना बनाया जा रहा है।

भोपाल होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष तेजकुल पाल सिंह पाली के मुताबिक, भोपाल के करीब 2 हजार होटल-रेस्टॉरेंट को 4 दिन में एक भी सिलेंडर नहीं मिला। कई होटल्स ऐसे हैं, जहां पर 24 से 48 घंटे तक भी बमुश्किल निकल पाएंगे।

एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि होटल, रेस्टॉरेंट, कॉलेज की कैंटीन को भी इमरजेंसी सेवा में शामिल किया जाए, क्योंकि भोपाल में ही करीब 2 लाख स्टूडेंट्स को यहां से भोजन मिलता है। उनके सामने बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी।

- श्योपुर में एसडीएम गगन मीणा ने माइक पर लोगों को समझाइश दी। भीड़ संभालने के लिए पुलिस तैनात।
- इंदौर में एजेंसी वाले बुकिंग के लिए नया नंबर दे रहे, एप डाउनलोड करवा रहे। रात में बुकिंग करने का कह रहे हैं।
- बालाघाट के वारासिवनी में खाद्य विभाग की टीम ने चौपाटी वालों से 13 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए।
- डिंडौरी की महिला कर्मचारी ने बताया, सुबह से लाइन में खड़ी हैं। घर में 2 दिन से खाना नहीं बना है।
- भोपाल में उपभोक्ताओं ने बताया, गैस एजेंसी के अफसरों और कर्मचारियों के मोबाइल नंबर बंद हैं। कई प्रयासों के बावजूद ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही है, इसलिए लोग सीधे एजेंसी पहुंच रहे हैं।
- बालाघाट के कैटरर्स का कहना है कि सिलेंडर नहीं मिल रहे। ऐसे में शादियों की बुकिंग रद्द करनी होगी।
- नरसिंहपुर में गैस एजेंसियों में लंबी कतारें लगी हुई थी।
- बालाघाट में गैस संकट, अपर कलेक्टर बोले- डीजल भट्टी का प्रयोग करें।
- दमोह में इंडक्शन की मांग में भारी उछाल; मांग पूरी करना मुश्किल।

भोपाल में गैस उपभोक्ता परेशान, बोले- लाइन में सिर्फ जनता खड़ी है

भोपाल में भी रसोई गैस को लेकर हालात खराब हैं। शहर की गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। गैस उपभोक्ता ज्ञानेंद्र तिवारी का कहना है कि सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि देश में गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है।उन्होंने कहा कि एजेंसियों के बाहर आम लोग घंटों लाइन में खड़े हैं, जबकि कोई अधिकारी या नेता-मंत्री यहां नजर नहीं आता। उनका आरोप है कि एजेंसी संचालक खुद गैस की कमी की बात कर रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

घरेलू गैस की किल्लत

चौराहे पर जलाया चूल्हा, सिलेंडर को माला पहनाकर श्रद्धांजलि, कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन

शाजापुर (नप्र)। घरेलू गैस की किल्लत को लेकर अब एमपी में धरना-प्रदर्शन और विरोध का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के शुजालपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की डिलेवरी में 8 दिन तक की वेटिंग और कामर्शियल सिलेंडर की सप्लाई बंद होने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पुलिस चौकी चौराहा पर चूल्हा जलाकर गैस सिलेंडर को माला पहनाई और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।

प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नाम नरेन्द्र, काम सरेंडर के नारे लगाए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नोटबंदी से लेकर अब गैस सिलेंडर तक आम जनता को कतारों में खड़ा कर परेशान किया जा रहा है। युवा कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष चिराग परमार ने कहा कि शहर में होटल और रेस्टोरेंट पर तवा रोटी मिलना बंद हो गई है। टिफिन सेंटर को भी सिलेंडर डिलेवरी नहीं मिलने से घर से दूर रहकर नौकरी करने वाले लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है।

चूल्हे खोदकर खाना बनाने की नौबत आ गई

परमार ने कहा कि शादी समारोहों में भी सिलेंडर नहीं मिलने से चूल्हे खोदकर खाना बनाने की स्थिति बन गई है। प्रदर्शन में ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष मंगल सिंह राठौड़, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रचना जैन, पूर्व पार्षद महेंद्र नाहर, देवेंद्र परमार, पार्षद बल्ला सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

प्रशासन के गैस उपलब्धता के दावों पर सवाल

पर्याप्त उपलब्धता के दावों पर सवाल उठा रहे लोग जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा सोशल मीडिया पर जिले के विभिन्न अनुभागीय अधिकारियों के वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें अधिकारी क्षेत्र में गैस सिलेंडर की पर्याप्त उपलब्धता का दावा कर रहे हैं। इस पोस्ट पर भी आम नागरिक सवाल खड़े कर रहे हैं। लोगों ने बताया कि वह गैस सिलेंडर के लिए किस तरह परेशान हो रहे हैं। वहीं कुछ यूज़र ने घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला भी उठाया। उन्होंने पोस्ट पर लिखा कि अधिकारी फील्ड में उतरकर निरीक्षण करें और कालाबाजारी पर नियंत्रण करें।

नहीं हो पा रही ऑनलाइन बुकिंग

उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस सिलेंडर की ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो पा रही है। कभी फोन कनेक्ट नहीं होता तो कभी सर्वर डाउन की समस्या हो रही है, जिस कारण उनकी बुकिंग ही नहीं हो पा रही है।

भिंड में गैस सिलेंडरों से भरी गाड़ी लूटने की कोशिश, गैस एजेंसियों में दहशत, सप्लाई ठप

भिंड (नप्र)। दुनिया के एक हिस्से में बढ़ रहे युद्ध के बादलों ने चंबल के भिंड जिले में रसोई गैस का संकट पैदा कर दिया है। जिले की गैस एजेंसियों में इस समय दहशत और अनिश्चितता का माहौल है। आलम यह है कि नया स्टॉक न आने के कारण कई संचालकों ने कमर्शियल सप्लाई पूरी तरह बंद कर दी है, वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को अब सिलेंडर के लिए करीब एक महीने का इंतजार करना पड़ रहा है।

25 दिन तक पहुंचा वेटिंग पीरियड- भिंड में गैस वितरण की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। एजेंसी संचालकों के मुताबिक, पहले बुकिंग के बाद 15 दिनों में मिलने वाला सिलेंडर अब 20 से 25 दिनों की देरी से मिल रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण नया स्टॉक न आना, सर्वर डाउन रहना और डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी कॉर्ड के माध्यम से होने वाली जटिल वितरण प्रक्रिया को बताया जा रहा है।

हाईवे पर सिलेंडर लूटने की कोशिश- सप्लाई की कमी ने असामाजिक तत्वों को सक्रिय कर दिया है। बीते 10 मार्च को मालनपुर और गोहद के बीच बालाजी को लूटने का प्रयास किया गया। इस सनसनीखेज वारदात के बाद साईं गैस एजेंसी समेत अन्य संचालकों ने डर के मारे सिलेंडरों से भरी गाड़ियों को गोदामों में ही खड़ा कर दिया है। वितरण ठप होने से आम जनता का गुस्सा कर्मचारियों पर फूट रहा है।

एजेंसी संचालक ने कहा युद्ध के हालातों के बीच सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। ऊपर से सिलेंडरों की सुरक्षा अब बड़ी चुनौती बन गई है। हमने प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है ताकि कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रशासन से सुरक्षा की गुहार- लगातार हो रही धक्का-मुक्की और लूट की घटनाओं से घबराए गैस एजेंसी संचालकों ने जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी से संपर्क किया है। संचालकों ने स्पष्ट किया है कि यदि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नहीं की गई और सप्लाई सामान्य नहीं हुई, तो आने वाले दिनों में गैस वितरण पूरी तरह ठप करना पड़ सकता है।

जूनियर डॉक्टर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी : उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल

उप मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुक्रम में स्टाइपेंड वृद्धि आदेश जारी, 1 अप्रैल 2025 से होंगे प्रभावशील

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल के निर्देशों के अनुपालन में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में वृद्धि संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि प्रदेश सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सशक्त एवं जनोन्मुख बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि जूनियर डॉक्टर पूर्ण समर्पण से प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त और सुदृढ़ करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभायेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि जूनियर डॉक्टर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में वे न केवल अपने चिकित्सा प्रशिक्षण को पूर्ण करते हैं। मरीजों को निरंतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में भी जूनियर डॉक्टर अग्रणी भूमिका निभाते हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने जूनियर डॉक्टर के हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित अधिकारियों को सकारात्मक समाधान के निर्देश दिए थे। उसके अनुक्रम में विभाग द्वारा स्टाइपेंड वृद्धि का आदेश जारी किया गया है। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत जूनियर डॉक्टरों के स्टाइपेंड में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2.94 के आधार पर वृद्धि करते हुए 1 अप्रैल 2025 से संशोधित स्टाइपेंड लागू किया गया है। इसके तहत पीजी प्रथम वर्ष का स्टाइपेंड 75,444 रुपये से बढ़ाकर 77,662 रुपये, द्वितीय वर्ष का 77,764 रुपये से बढ़ाकर 80,050 रुपये तथा तृतीय वर्ष का 80,086 रुपये से बढ़ाकर 82,441 रुपये किया गया है। इसी प्रकार इंटर्न का स्टाइपेंड 13,928 रुपये से बढ़ाकर 14,337 रुपये किया गया है। सुपर स्पेशिलिटी पाठ्यक्रम के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के स्टाइपेंड को भी बढ़ाकर 82,441 रुपये निर्धारित किया गया है।

ग्वालियर के तिघरा ट्रेनिंग सेंटर से राजस्थान पुलिस के 36 जवान भेजे गए वापस

एआई वीडियो बनाकर कर रहे थे बदनाम

ग्वालियर (एजेंसी)। मध्यप्रदेश के ग्वालियर में प्रशिक्षण ले रहे राजस्थान पुलिस के 36 प्रशिक्षुओं को वापस भेज दिया गया है। सभी ने कथित तौर पर एआई का इस्तेमाल कर तस्वीरें बनाने और उन्हें सोशल मीडिया पर प्रसारित कर खराब खाना परोसे जाने का आरोप लगाया था। इसके बाद इन्हें ट्रेनिंग सेंटर से वापस भेज दिया गया है।

ट्रेनिंग सेंटर को बदनाम किया- एमपी के एडीजी राजा बाबू सिंह ने कहा कि जांच में पता चला कि शरारती रंगरूट एआई-जनित तस्वीरों का उपयोग करके तिघरा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र (पीटीसी) को बदनाम करने के लिए अभियान चला रहे थे। सिंह ने बताया कि उन्होंने कथित तौर पर एआई की मदद से तस्वीरें बनाई थीं, जिसमें प्रशिक्षण केंद्र में परोसा गया कथित बासी भोजन दिखाया गया था।

36 जवान अनुशासनहीनता में सही पाए गए

उन्होंने कहा कि 36 जवान ने अपनी नापाक, शरारती और घोर अनुशासनहीनता के साथ कथित तौर पर प्रशिक्षण केन्द्र के लिए समस्याएं पैदा कीं। इन जवानों में से ज्यादातर राजस्थान पुलिस की दूरसंचार शाखा से संबद्ध हैं। अधिकारी ने बताया कि पीटीसी ने नौ महीने के कांस्टेबल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए आए रंगरूटों को राजस्थान पुलिस निरीक्षक सतवीर यादव को सौंप दिया, जो उनलोगों को गुरुवार को उनके राज्य वापस ले गए।

राजस्थान के 1005 रंगरूटों को दे रहे थे प्रशिक्षण

सिंह ने कहा कि राजस्थान के डीजीपी के अनुरोध के बाद, 1,005 रंगरूटों को प्रशिक्षण केंद्र में भर्ती किया गया था और अब उनमें से 36 को वापस भेज दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार, राजस्थान पुलिस ने भर्ती किए गए कर्मियों से अधिक लोगों के लिए भोजन तैयार करने में पीटीसी की सहायता के लिए केवल दो रसोइयों को तैनात किया था और उनकी निगरानी के लिए स्थायी रूप से कोई अधिकारी भी तैनात नहीं किया था। उन्होंने बताया कि भर्ती किए गए लोग प्रशिक्षण केंद्र में मशीन से बने व्यंजनों के बजाय गट्टे की सब्जी, केर-संगरी और भट्टी की रोटियां सहित पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों की मांग कर रहे थे। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।

डंपर ने मासूम को कुचला... मां ने हाथ से समेटे टुकड़े

स्कूल की दीवार पर छिटके खून के छींटे; परिवार ने सड़क पर लगे ब्लड को धोया

मंडला (नप्र)। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शुक्रवार को तेज रफ्तार डंपर ने ढाई साल की बच्ची को कुचल दिया। हादसा इतना भयंकर था कि बच्ची के खून के छींटे स्कूल की दीवार पर पड़े हैं। बच्ची की डेडबॉडी सड़क पर चिपक गई थी। मां और परिजन ने टुकड़ों को हाथों से समेटकर पॉलीथीन में डाला। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

जानकारी के मुताबिक मृत बच्ची की पहचान आकृति यादव के रूप में हुई है, जो ग्राम बम्होरी की रहने वाली थी। वह आंगनवाड़ी से लौट रही थी, तभी हादसे का शिकार हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने चक्काजाम कर दिया है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है।

स्थानीय लोगों ने बताया कि करीब एक बजे आंगनवाड़ी सहायिका श्रृष्टि यादव बच्चों को केंद्र से छोड़कर घर की ओर जा रही थीं। उनके साथ गोद में एक छोटा बच्चा था, जबकि ढाई वर्षीय आकृति उनका हाथ पकड़कर पैदल चल रही थी। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। वीडियो में दिख रहा है कि बच्ची की डेडबॉडी सड़क किनारे पड़ी है। सड़क पर लोगों की भीड़ है। मां और अन्य परिजन मौके पर हैं। मां चीख-चीखकर रो रही है। वहीं परिजन सड़क पर बच्ची के खून को पानी से धुलते नजर आ रहे थे।

हादसे के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। इसके बाद ग्रामीणों ने बाइक, ट्रैक्टर और अन्य वाहनों से डंपर का पीछा किया। करीब 7 किलोमीटर दूर तिंदनी टोल प्लाजा के पास डंपर को पकड़ लिया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया।

ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत, दो स्कूली छात्रों की मौत

सागर में परीक्षा देकर लौट रहे थे, बाइक चला रहे सरपंच पिता और बेटा गंभीर घायल

सागर (नप्र)। सागर के रहली थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरगौर-खिरिया रोड़ पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक ट्रैक्टर के नीचे फंस गई। घटना में बाइक पर सवार दो स्कूली बच्चों की मौत हो गई। वहीं बाइक चला रहे पिपरगौर के सरपंच और उनका बड़ा बेटा गंभीर घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त किया है।

जानकारी के अनुसार, रहली के पटना बुजुर्ग में स्थित क्राइस्ट कॉन्वेंट स्कूल में अभिजीत पिता राजेंद्र सिंह (15), विश्वजीत पिता राजेंद्र सिंह (11) और शिवाय पिता सोहन (10) निवासी पिपरगौर पढ़ाई कर रहे थे। उनकी वार्षिक परीक्षा चल रही थी। शुक्रवार को पेपर दिलाने के लिए पिपरगौर के सरपंच पिता राजेंद्र पिता राजकुमार सिंह (47) अपने बेटे अभिजीत, विश्वजीत और भतीजे शिवाय को स्कूल लेकर परीक्षा दिलाने गए थे।

स्कूल में पेपर होने के बाद वापस घर लौट रहे थे, तभी पिपरगौर के पास सामने से आ रहे ईंट से भरे ट्रैक्टर-ट्राली से बाइक की भिड़ंत हो गई। टक्कर में बाइक ट्रैक्टर के नीचे फंस गई। घटना में गंभीर चोटे लगने से विश्वजीत और शिवाय की मौत हो गई। वहीं सरपंच पिता राजेंद्र सिंह और बेटा अभिजीत गंभीर घायल हुए। घायलों को रहली स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रैफर किया गया है।

परिवार का इकलौता बेटा था शिवाय

दुर्घटना में मृत हुआ छात्र शिवाय अपने परिवार का इकलौता बेटा था। उसके पिता की मौत करीब 5 साल पहले हो चुकी थी। बेटे की मौत के बाद परिवार में मातम का माहौल है। घायल अभिजीत कक्षा 9वीं की पढ़ाई कर रहा है। वहीं मृत विश्वजीत कक्षा 7वीं और शिवाय कक्षा चौथीं की पढ़ाई कर रहा था। मामले में पुलिस ने शवों का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम कराया है। मामला दर्ज कर ट्रैक्टर-ट्राली को जब्त किया गया है। ड्राइवर मौके से भाग गया। जिसकी तलाश की जा रही है।

चाकू से युवक का कान काटा...12 घंटे से बेहोश

बदमाशों ने सिर-गर्दन पर वार किए; आरोपी बोले थे-ऐसा मारेंगे नजीर बना जाओगे

भोपाल (नप्र)। भोपाल में बदमाशों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में युवक का दांया कान कट गया। उसके सिर और गर्दन पर भी वार किए गए हैं। खून से लथपथ युवक को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक घायल की पहचान अल्ताफ राजा के रूप में हुई है, जो ऐशबाग क्षेत्र का रहने वाला है। चौक बाजार से घर लौटते समय नूर महल रोड पर आरोपी अमन नेपाली और उसके साथियों ने घेरकर मारा। आरोपियों ने कहा था कि तुझे ऐसा मारेंगे कि नजीर बन जाएगा।

रात करीब 10 बजे वारदात- कोतवाली पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात करीब 10 बजे वारदात हुई है। आरोपियों ने जमकर आतंक मचाया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। अल्ताफ के शरीर से काफी ज्यादा खून बह गया है, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

कोतवाली टीआई काशीराम कुशवाह ने बताया कि घायल अल्ताफ राजा ऑटो-डीलिंग का काम करता है। गर्दन में ज्यादा घाव लगने की वजह से 12 घंटे से वह बेहोश है। डॉक्टर्स की निगरानी में इलाज चल रहा है। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया है।

पुराने मामले में समझौता नहीं करने पर अटैक- कोतवाली पुलिस के मुताबिक आरोपी अमन नेपाली पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अल्ताफ पर समझौता करने का दबाव बना रहा था, लेकिन उसने समझौते से इनकार कर दिया था। इसके बाद अमन ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमले की साजिश रची।

पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फरार आरोपियों की तलाश में उनके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।